रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने यूक्रेन में हमले के लिए लगातार दूसरी बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यह हमला काला सागर तट पर मौजूदा यूक्रेन के ईंधन डिपो पर किया गया..

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्ष:27 अंक: 96 दिनांक: 21-03-2022 सोमवार मूल्य : 100 पैसा पृष्ठ:4 अहमदाबाद M

मणिपुर में रविवार को भाजपा विधायकों ने निवर्तमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को अपना नेता चुन लिया, यानी वह ही दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री होंगे।

थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल दामों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। महंगाई के उछाल का असर डीजल पर भी पड़ने वाला है। अब थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि थोक ग्राहकों को बिक्री वाला डीजल 25 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40 प्रतिशत के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि, पेट्रोल पंपों के जरिये बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस महीने पेट्रोल पंपों की बिक्री में 20 प्रतिशत का उछाल आया है। बस बेड़े के परिचालकों और मॉल जैसे थोक उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदा है। आमतौर पर वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे ईंधन की खरीद करते हैं। इससे ईंधन की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनियों का नुकसान बढ़ा है।

सबसे अधिक प्रभावित नायरा एनर्जी, जियो-बीपी और शेल जैसी कंपनियां हुई हैं। बिक्री बढ़ने के बावजूद इन कंपनियों ने अभी तक मात्रा में कमी नहीं की है। लेकिन अब पंपों के लिए परिचालन आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने कहा कि रिकॉर्ड 136 दिन से ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए इन दरों पर अधिक ईंधन बेचने के बजाय पेट्रोल पंपों को बंद करना अधिक व्यावहारिक विकल्प होगा। वर्ष 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिक्री घटकर 'शून्य' पर आने के बाद अपने सभी 1,432 पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। सूत्रों ने कहा कि कुछ यही स्थिति आज भी बन रही है। थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं। इससे इन रिटेलरों का घाटा बढ़ रहा है।

मुंबई में थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल का दाम बढ़कर 122.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल पंपों पर डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। इसी तरह दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर है जबकि थोक या औद्योगिक ग्राहकों के लिए इसकी कीमत 115 रुपये प्रति लीटर है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने चार नवंबर, 2021 से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं हालांकि, इस दौरान वैश्विक स्तर पर ईंधन कीमतों में उछाल आया है। माना जा रहा है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की वजह से फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। थोक और पेट्रोल पंप कीमतों में 25 रुपये के बड़े अंतर की वजह से थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं। वे पेट्रोलियम कंपनियों से सीधे टैंकर बुक नहीं कर रहे हैं। इससे पेट्रोलियम कंपनियों का नुकसान और बढ़ा है।

गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरियां बनाने 10,445 करोड़ निवेश करेगी सुजुकी

नई दिल्ली (ईएमएस)। जापान की वाहन कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (एसएमसी) 2026 तक गुजरात में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) तथा बीईवी बैटरियों के स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए 150 अरब येन (10,445 करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। कंपनी ने इस बारे में गुजरात सरकार के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने कहा ?कि इस करार पर नई दिल्ली में 19 मार्च, 2022 को आयोजित भारत-जापान आर्थिक मंच में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। मंच को संबोधित करते हुए एसएमसी के प्रतिनिधि निदेशक एवं अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने कहा ?कि सुजुकी का भविष्य का मिशन छोटी कारों के साथ कॉर्बन निरपेक्षता हासिल करने का है। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए यहां लगातार निवेश जारी रखेंगे। एमओयू के तहत कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट ?लिमिटेड 2026 तक एसएमसी के मौजूदा कारखाने के पास बीईवी बैटरियों के विनिर्माण संयंत्र पर 7,300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा एसएमसी 2025 तक बीईवी विनिर्माण की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी 3,100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। समूह की एक अन्य कंपनी मारुति सुजुकी तोयोत्सु इंडिया प्राइवेट ?लिमिटेड 2025 तक वाहन रिसाइक्लिंग संयंत्र के निर्माण पर 45 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी।

चार राज्यों में सरकार गठन पर मंथन

मणिपुर में बीरेन सिंह को फिर मौका, गोवा में प्रमोद सावंत पहली पसंद, उत्तराखंड में धामी आगे

नई दिल्ली। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सोमवार को पता चल जाएगा। शाम पांच बजे उत्तराखंड के पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में देहरादून में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। संकेतों से साफ है कि चुनाव हारने के बावजूद इस दौड़ में निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अन्य दावेदारों से आगे हैं। गोवा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक भी सोमवार को अपना नेता चुन लेंगे, वहां भी निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लगने की संभावना है।

मणिपुर में बीरेन सिंह होंगे सीएम

मणिपुर में रविवार को भाजपा विधायकों ने निवर्तमान मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को अपना नेता चुन लिया, यानी वह ही दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों की गुरुवार को बैठक होनी है जिसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगना महज औपचारिकता है। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

दिल्ली में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उत्तराखंड और केंद्रीय नेताओं के बीच अंतिम दौर का विचार-विमर्श हुआ। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने शाम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में जानकारी दी। बैठकों के बाद मिले संकेतों से साफ है कि चुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में धामी अन्य दावेदारों से आगे हैं। अन्य नाम भी चर्चा में हैं जिनमें सतपाल महाराज, धन उसह रावत और ऋतु खंडूड़ी शामिल हैं। केंद्रीय नेतृत्व के साथ नजदीकियों के कारण राज्यसभा सदस्य व भाजपा के केंद्रीय मीडिया सेल के प्रमुख अनिल बलूनी के नाम को भी नकारा नहीं जा रहा है।

सोमवार को प्रस्तावित विधायक दल की बैठक से पहले रविवार को भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली पहुंचे। अमित शाह के घर पर हुई बैठक में धामी और कौशिक के अलावा उत्तराखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। नड्डा और संतोष ने भी बैठक में हिस्सा लिया। लगभग एक घंटे चली बैठक के बाद धामी ने कहा कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। वहीं, मदन कौशिक ने बताया कि सभी नेताओं से सुझाव लिए गए हैं। बैठक के बाद देहरादून रवाना होने से पहले धामी ने निशंक से उनके घर जाकर मुलाकात की।

दिनभर चली बैठकों के बावजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से कोई एक नाम सामने नहीं आ पाया। इसके लिए सोमवार को प्रस्तावित विधायक दल की बैठक का इंतजार करना होगा। मालूम हो कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतने के बाद भी धामी की हार के कारण मुख्यमंत्री पद की गुत्थी उलझ गई थी। तमाम कयासों के बावजूद भाजपा के लिए उत्तराखंड में ज्यादा प्रयोग की गुंजाइश नहीं है। दो मुख्यमंत्रियों पर प्रयोग करने के बाद आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व ने पिछले साल धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी थी। धामी भले ही अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन भाजपा की जीत में उनका योगदान नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि राज्य के दिग्गज नेताओं के दावे के बावजूद धामी मुख्यमंत्री पद की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं।

मणिपुर में बीरेन सिंह के नाम पर मुहर लगना आसान नहीं था क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ विधायक बिश्वजीत सिंह ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए कड़ी दावेदारी पेश की थी। इसी तरह गोवा में प्रमोद सावंत के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता विश्वजीत राणे चुनौती पेश कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने शनिवार को शाह, नड्डा और संतोष से मुलाकात भी की थी।

कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं : संजय राउत

नई दिल्ली (ईएमएस)। जब से कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके दर्द पर केंद्रित फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, तब से पूरे देश में इसे लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ फिल्म का भारी समर्थन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस फिल्म का भारी विरोध भी किया जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर को ऐसी किसी भी स्थिति से अलग रखा जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक फिल्म है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी पार्टी को आने वाले चुनावों में किसी तरह का फायदा मिलेगा। संजय राउत ने कहा जब तक चुनाव आएंगे तब तक फिल्म भी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है इसलिए इस पर राजनीति करना सही नहीं है।

इमरान ने विपक्ष को गलत नीतियों पर घेरते हुए भारत की विदेश नीति को लोगों के हित की नीति करार दिया

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद इलाके में एक सार्वजनिक सभा के दौरान इमरान खान ने भारत की तारीफ शुरू कर दी। पाक पीएम ने विपक्ष को गलत नीतियों पर घेरते हुए हिंदुस्तान की विदेश नीति को लोगों के हित की नीति करार दिया। इतना ही नहीं उन्होंने बड़े देशों के विवाद में भारत को इशारों में तटस्थ तक कह दिया।

इमरान खान ने रैली के दौरान कहा, ठसाथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद विदेश नीति रखी है। आज हिंदुस्तान उनके साथ (बड़ी ताकतों के साथ) मिला हुआ है। उनके साथ अलायड है। इमरान ने आगे कहा, ठहिंदुस्तान क्वाड के अंदर अमेरिका का सहयोगी है और अपने आप को कहता है कि मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है, जबकि प्रतिबंध लगे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की नीति अपने लोगों की नीति है।ठ

गौरतलब है कि यूक्रेन को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच छिड़े तनाव को लेकर भारत ने अब तक किसी का पक्ष नहीं लिया है। हालांकि, भारत की तरफ से युद्ध को खत्म करने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की मांग की जाती रही है। जहां पश्चिमी देशों ने एक के बाद एक यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर प्रतिबंधों का एलान किया है, तो वहीं भारत ने अपने पुराने संबंधों और तटस्थता का परिचय देते हुए रूस के साथ व्यापार जारी रखा है।

अब आठ सप्ताह बाद ही लग सकेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज, ऊँउइ ने की सिफारिश

नई दिल्ली । कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी एनटागी ने कोविशील्ड की दूसरी डोज आठ से 16 हफ्ते के बीच लगाने की सिफारिश की है। अभी इस वैक्सीन की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बीच लगाई जा रही है। एनटागी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दो डोज के बीच अंतराल में किसी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जाती है। कोविशील्ड की दो डोज में अंतराल की सिफारिश को अभी लागू किया जाना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वैश्विक आंकड़ों से तैयार वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतराल में बदलाव करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने बताया कि आठ से 16 हफ्ते के बीच दूसरी डोज लगाने के बाद भी एंटीबाडी का स्तर उसी तरह का होगा जैसा कि 12 से 16 हफ्ते के बीच दूसरी डोज देने पर है। इस सिफारिश को लागू करने के बाद दूसरी डोज लगाने में तेजी आएगी, क्योंकि देश में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड ही लगाई जा रही है।

शुरू में कोविशील्ड की दो डोज के बीच अंतराल को छह से आठ हफ्ते का रखा गया था। इसका मतलब है कि पहली डोज लेने के दिन से छह से आठ हफ्ते के भीतर दूसरी डोज लेनी जरूरी थी। एनटागी की सिफारिश पर पिछले साल 13 मई को अंतराल को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया था। ज्ञात हो कि करीब एक महीने ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया (डीजीसीआइ) ने कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड को कुछ शर्तों के साथ वयस्कों के लिए बाजार में लाने की अनुमति दी है, लेकिन वैक्सीन अभी बाजार में नहीं मिलेगी। डीजीसीआइ की शर्तें सिर्फ डाक्टरों के क्लीनिक और नर्सिंगहोम ही पूरी कर सकेंगे। इसलिए वैक्सीन दवा दुकानों में नहीं उपलब्ध होगी।

डाक्टर के क्लीनिक और नर्सिंगहोम से खरीद कर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। इसके लिए वैक्सीन का पूरा रिकार्ड रखना होगा। इस अनुमति के बाद डाक्टरों के क्लीनिक व नर्सिंगहोम में कोवैक्सीन व कोविशील्ड की एक डोज 275 रुपये में मिलेगी। वैक्सीन लगवाने का सर्विस चार्ज 150 रुपये भी देना होगा। इस हिसाब से वैक्सीन की एक डोज 425 रुपये में मिलेगी।

सूत्र ने कहा कि कई देशों में बढ़ते मामलों के बीच इस फैसले से प्रशासन द्वारा शेष छह से सात करोड़ व्यक्तियों को कोविशील्ड की दूसरी खुराक का तुरंत लगाई जा सकेगी। सरकार ने 13 मई, 2021 को एनटीएजीआई की सिफारिशों के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतर को 6-8 सप्ताह से बढ़ाकर 12-16 सप्ताह कर दिया था। एनटीएजीआई देश में वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य बीमारियों के प्रभावी नियंत्रण के लिए टीकाकरण की सेवाओं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है।

अखिलेश की दुविधा विधायक रहें या सांसद अब पार्टी पर छोड़ा फैसला

आजमगढ़ (ईएमएस)। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से विधायक रहेंगे या फिर आजमगढ़ के सांसद पद से इस्तीफा देंगे इसका फैसला अगले कुछ दिनों में होगा। शनिवार को सैफई में अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और एमएलसी के चुनावों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह विधायक रहेंगे या सांसद इसका फैसला अगले कुछ दिनों में करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करहल से विधायक अखिलेश यादव ने मैनपुरी के पार्टी नेताओं को सैफई में बुलाया था। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ मैनपुरी की दो सीटों पर हार के कारणों की चर्चा की। सपा इस बार के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर और भोगांव सीट पर चुनाव हार गई है। अपने ही गढ़ में दो सीटों पर चुनाव हारने से सपा की प्रतिष्ठा को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हिम्मत न हारने की अपील करते हुए कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए फिर से मेहनत करनी है। फिलहाल पार्टी के नेता पार्टी के एमएलसी पद के दोनों प्रत्याशियों को मैनपुरी से जिताने में जुटें। मैनपुरी के नेताओं ने अखिलेश यादव से कहा कि वह करहल सीट से इस्तीफा न दें। वह करहल विधायक बने रहें। कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा कि वे आजमगढ़ से सांसद रहेंगे या फिर करहल से विधायक बने रहेंगे इसका फैसला पार्टी की बैठक में लिया जाएगा। आगामी 26 मार्च को सभी विधायकों की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में इस बात का फैसला हो जाएगा कि अखिलेश विधायक रहेंगे या सांसद पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते संभावना इस बात की ज्यादा है कि अखिलेश करहल से इस्तीफा दे सकते हैं और आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे।

25 साल बाद एक हुए आरजेडीऔर एलजेडी

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार की राजनीति के दो बड़े नाम 25 साल के बाद फिर एक हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने रविवार को घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो गया है। हालांकि, खास बात है कि साल 2018 में गठन के बाद से ही लोजद ने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। राजद के साथ हमारी पार्टी का विलय विपक्षी एकता की ओर पहला कदम है। यह जरूरी है कि भारत भर में पूरा विपक्ष भाजपा को हराने के लिए एक हो जाए। फिलहाल, एकता स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद ही हम सोचेंगे कि विपक्ष एकता का नेतृत्व कौन करेगा। इससे पहले बुधवार को भी यादव ने कहा था, 'देश में मजबूत विपक्ष स्थापित करना समय की मांग है।मैं इस दिशा में न केवल बिखरी हुई तत्कालीन जनता दल बल्कि अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं और इसीलिए अपनी पार्टी एलजेडी का राजद में विलय करने का फैसला किया।' राजद नेता और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शरद को पिता समान बताया था और कहा था कि भारतीय राजनीति में सभी लोग उनकी अहमियत जानते हैं। खास बात है कि दशकों लंबे करियर में कई बार लालू और शरद का सियासी आमना-सामना हुआ। हालांक, दोनों नेताओं के बीच जनता दल के समय से ही घनिष्ठता देखी गई थी। फिलहाल, भ्रष्टाचार मामलों में सजा काट रहे लालू ने 1997 में जनता दल से किनारा कर लिया था और राजद का गठन किया था। साल 2005 में नीतीश कुमार और शरद यादव ने मिलकर बिहार चुनाव अपने नाम किया और राजद को सत्ता से बाहर कर दिया था।

केंद्र सरकार ने शुरू की क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने अब क्रिप्टोकरेंसी को भी जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार माल एवं सेवा कर कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर टैक्स लगाया जा सके। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है और इसे वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जीएसटी अधिकारियों का विचार है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान हैं, जिनके पूरे मूल्य पर 28 फीसद जीएसटी लागू है। इसके अलावा सोने के मामले में पूरे लेनदेन मूल्य पर तीन फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरे मूल्य पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है, तो यह दर 0.1 से एक फीसदी के बीच हो सकती है। अधिकारी ने कहा टैक्स की दर पर चर्चा शुरुआती चरण में है, चाहे यह 0.1 फीसदी हो या एक फीसदी। पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी।

जीएसटी कानून क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और ऐसी वर्चुअल डिजिटल मुद्राओं को विनियमित करने के लिए कानून के अभाव में वर्गीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कानूनी ढांचा इसे अनुयोज्य दावे के रूप में वर्गीकृत करता है या नहीं। अनुयोज्य दावा एक ऐसा दावा है, जो न्यायालय में कार्रवाई के योग्य हो। आम बजट 2022-23 में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में कुछ स्पष्टता लाई गई है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए अलग से एक कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है।

बीजेपी में अभी लड़ाई-झगड़े ही चल रहे, भगवंत मान ने शपथ लेकर काम भी शुरू कर दिया: अरविंद केजरीवाल

मोहाली (ईएमएस)। पंजाब में आप सरकार बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को वर्चुअल मीटिंग की। पंजाब आप विधायक वर्चुअल मीटिंग के लिए मोहाली के एक होटल में पहुंचे। मीटिंग में केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ पंजाब में भगवंत मान ने शपथ भी ले ली, उनकी ओर से काम भी शुरू हो गए। दूसरी तरफ भाजपा जो 4 राज्यों में जीती थी, उनसे सरकार तक नहीं बन पाई है। अभी उनके लड़ाई-झगड़े ही चल रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, ठभगवंत मान ने 16 तारीख को शपथ ली, 3 दिनों में ही लोगों को काम करके दिखाया। पुराने मंत्रियों की सुरक्षा हटाकर उसे जनता के लिए लगाया गया। अक्टूबर में फसलें बर्बाद हुई थी, उसका मुआवजा किसानों के जिलों में पहुंच गया। 3-4 दिनों में किसानों को उसका चेक मिलेगा। पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की गई। 25,000 नौकरियों का ऐलान किया गया, इससे लोगों की हमसे उम्मीद अब विश्वास में बदलती जा रही है।ठ आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों से कहा, ठभगवंत मान हर मंत्री को टारगेट देंगे और उन्हें तय समय सीमा के अंदर पूरा करना होगा। मंत्रियों को दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो जनता कहेगी कि मंत्री बदलो। आप सभी को भगवंत मान के नेतृत्व में मिलकर काम करना है। मार्गदर्शन देने के लिए मैं आपके बड़े भाई के समान रहूंगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मान ने कहा, ठपंजाब के हर दूसरे व्यक्ति ने हमें वोट दिया है, तो ये प्यार हम पंजाब के लोगों के लिए ही लगाएंगे। पहले ये होता था कि ऑर्डर कोई और देता था, सस्पेंड कोई और होता था, ये अब नहीं चलेगा। हमने 25,000 नौकरियों का वादा किया है। एक महीने के भीतर भर्तियां निकलेंगी।

जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार : गुलाम नबी आजाद

जम्मू (ईएमएस)। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने महात्मा गांधी सबसे बड़ा हिंदू और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया। आजाद ने कहा, ठमेरा मानना है कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और धर्मनिरपेक्ष थे। जम्मू-कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार हैं। इसने सभी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, डोगराओं को प्रभावित किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राजनीतिक दल धर्म, जाति और अन्य चीजों के आधार पर चौबीसों घंटे विभाजन पैदा कर सकते हैं। मैं किसी भी पार्टी को माफ नहीं कर रहा हूं। लोगों को समाज में साथ रहना चाहिए। जाति, धर्म के बिना सभी को न्याय मिलना चाहिए। दरअसल, बॉलीवुड फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के चलते जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। फिल्म पर एक के बाद एक बाद राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। ताजा बयान शिवसेना नेता संजय राउत का आया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर एक फिल्म बनी है, लेकिन सच छुपाया गया है। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को विवेक रंजन अग्निहोत्री ने निर्देशित किया है। फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन रावल, पल्लवी जोशी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों ने काम किया है। 'द कश्मीर फाइल्स' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया है। फिल्म को 'बाहुबली-2' जैसी पॉपुलैरिटी मिली है और कई मायनों में यह फिल्म एस.एस. राजामौली की फिल्म को टक्कर दे रही है। फिल्म को रिलीज हुए तकरीबन डेढ़ हफ्ते का वक्त हो चुका है और बहुत जल्द ये फिल्म 150 करोड़ क्लब में कदम रखने जा रही है। फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 141 करोड़ 25 लाख रुपये हो चुका है।

कार्टून कोना

'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज पर न्यूजीलैंड में रोक

नई दिल्ली (ईएमएस)। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज पर न्यूजीलैंड में रोक लगा दी गई है। देश के सेंसर बोर्ड, जिसने पहले फिल्म को मंजूरी दी थी, ने कुछ सामुदायिक समूहों द्वारा संपर्क किए जाने के बाद अपने फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया।

देश के सेंसर बोर्ड ने 'द कश्मीर फाइल्स' को एक सर्टिफिकेट दिया था जो 16 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को इसे देखने की अनुमति देता है। लेकिन बोर्ड ने अपने फैसले की समीक्षा करने और फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है।

1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर केंद्रित यह फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिर गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा फिल्म की सामग्री पर चिंता जताए जाने के बाद मुख्य सेंसर फिल्म के वर्गीकरण की समीक्षा कर रहा है।

न्यूजीलैंड के पूर्व उप प्रधान मंत्री विंस्टन पीटर्स ने फिल्म बोर्ड पर निशाना साधा और कहा कि फिल्म को सेंसर करना न्यूजीलैंड के लोगों की स्वतंत्रता पर हमला होगा।

पीटर्स ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ठइस फिल्म को सेंसर करना न्यूजीलैंड में 15 मार्च के अत्याचारों की जानकारी या छवियों को सेंसर करने के समान है, या उस मामले के लिए 9/11 पर हमले की सभी छवियों को सार्वजनिक ज्ञान से हटा देना है।ठ

उन्होंने कहा, ठआतंकवाद अपने सभी रूपों में, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, उजागर किया जाना चाहिए और इसका विरोध किया जाना चाहिए। चयनात्मक सेंसरशिप के इस प्रयास से न्यूजीलैंड और दुनिया भर के लोगों की स्वतंत्रता पर एक और हमला होगा।

लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की श्रेणी में पीएम मोदी ने स्थान पाया

-13 वैश्विक नेताओं के अप्रूवल रेटिंग चार्ट में रहे अव्वल

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी 77 फीसद अप्रूवल के साथ शीर्ष पर हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर में वयस्कों के बीच सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। वहीं भाजपा ने ट्वीट कर लिखा कि वैश्विक नेताओं की तुलना में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 77 फीसद ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले पायदान पर। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है।

अमेरिका में मौजूद ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट ने वैश्विक नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग सबसे अधिक है और वह 77 फीसद अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। 18 मार्च को मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने अपना लेटेस्ट डेटा जारी किया। इसमें कहा गया कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 13 देशों के नेताओं में सबसे अधिक है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी अधिक है।

रिसर्च कंपनी द्वारा किए गए सर्वे में दुनिया के 13 नेताओं में पीएम मोदी 77 फीसद अप्रूवल रेटिंग के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद मेक्सिको के एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर का नंबर आता है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 63 फीसद है। इटली के मारिया द्राघी की अप्रूवल रेटिंग 54 फीसद है। वहीं, जापान के फुमियो किशिदा को 45 फीसद की अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी की डिसअप्रूवल रेटिंग भी सबसे कम 17 फीसद है। डेटा से पता चलता है कि भारतीय प्रधानमंत्री जनवरी 2020 से मार्च 2022 तक अधिकांश महीनों के लिए सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने रहे। लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग 9 से 15 मार्च 2022 तक इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग उनके राष्ट्रपति बने रहने के दौरान सबसे कम हो गई है। पिछले साल कोविड-19 मौतों में वृद्धि और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी की वजह से बाइडेन की लोकप्रियता गिरना शुरू हो गई थी। यूक्रेन संकट और देश में चल रही अन्य समस्याओं की वजह से बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग आने वाले दिनों में और गिर सकती है। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक, सर्वे किसी दिए गए देश में सभी वयस्कों के सात-दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित रीयल-टाइम डेटा को दर्शाता है, जिसमें मार्जिन ऑफ एरर 1 से 3 फीसद के बीच होता है। अमेरिका में औसत नमूना आकार 45,000 है, जबकि अन्य देशों में यह लगभग 3,000-5,000 के बीच है।

जन हितैषी

बदला सियासी नक्शा

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। नतीजे भाजपा के लिए उत्साहजनक हैं, तो विपक्ष के लिए निराशाजनक। यह तय है कि इन नतीजों के बाद विपक्ष को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और जनता के बीच अपनी छवि बदलनी होगी। राजनीति का ट्रेंड अब बिल्कुल बदल चुका है। पुरानी धारा पर चुनाव जीतना अब मुश्किल है। अब विकास की बात होती है, जातियों की नहीं। पांच राज्यों में परिणाम आने के बाद देश का सियासी नक्शा बदल गया है। फिलहाल 18 राज्यों में भाजपा और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। इन राज्यों में देश की करीब 50 फीसदी फीसदी आबादी रहती है। यानी, देश की करीब आधी आबादी वाले राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। वहीं, छह राज्यों में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। जहां देश की करीब 28 फीसदी आबादी रहती है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी के सत्ता में आने के वक्त देश के सात राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। इनमें पांच राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। वहीं, बिहार और पंजाब में उसकी सहयोगी पार्टी सरकार चला रही थी। इन दो राज्यों में देश की 11 फीसदी से ज्यादा आबादी रहती है। बाकी पांच राज्यों छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा के मुख्यमंत्री थे। इन राज्यों में देश की 19 फीसदी आबादी रहती है। यानी, जब मोदी सत्ता में आए उस वक्त करीब 30 फीसदी आबादी पर भाजपा और उसकी सहयोगी सरकारें चल रही थीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उस वक्त देश के 14 राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। कांग्रेस शासित इन राज्यों में देश की 27 फीसदी से ज्यादा आबादी रहती है। इन राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे दो बड़े राज्य शामिल थे। 2014 में सात राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। चार साल बाद मार्च 2018 में 21 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार थी। इन राज्यों में देश की करीब 71 फीसदी आबादी रहती है। ये वो दौर था जब भाजपा शासन आबादी के लिहाज से पीक पर था। वहीं, चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। इन राज्यों की सात फीसदी आबादी रहती है। भाजपा इस वक्त करीब 50 फीसदी आबादी पर राज कर रही है। भाजपा तो 18 राज्यों में अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य चला गया। अभी कांग्रेस और गठबंधन की छह राज्यों में सरकार है। पंजाब हाथ से जाने के बाद पांच राज्यों में ही सरकार रह जाएगी। इनमें भी केवल दो राज्य ऐसे हैं, जहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मतलब यहां इनके मुख्यमंत्री हैं। जबकि अन्य तीन राज्यों में गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस को इस प्रदर्शन से सबक लेना होगा। उसके सामने 2023 का लोकसभा चुनाव है। इससे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चुनाव मैदान में जाना है। इन सभी जगहों पर उसका मुकाबला भाजपा से होना है, जिसके पास कैडर है, कार्यकर्ताओं की भारी फौज है। अगर कांग्रेस इसी तरह चुनाव लड़ती रहेगी, तो आप जैसे दल उससे सत्ता छीनते रहेंगे। आप को पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर से भारी लाभ हुआ है। आप को उन युवा और महिला मतदाताओं का समर्थन मिला जो एक नई पार्टी को मौका देना चाहते थे। पिछले चुनाव में यही वर्ग कांग्रेस के साथ आया था, मगर इस बार कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने इस वर्ग को दूर कर दिया। कुल मिलाकर भाजपा को इस जीत से बड़ा टॉनिक मिला है। वह पूरे देश में प्रचारित करेगी कि विकास के नाम पर जनता उसके साथ है। जातियों की राजनीति अब पीछे छूट चुकी है।

आज का अहम सवाल - घुटने से फटी पैंट सही या हिजाब....?

अब पहली बार ऐसा लगने लगा है कि देश में साम्प्रदायिक धुवीकरण अब दक्षिण राज्यों से आ रहा है, अभी तक इसके लिए हिन्दी और हिन्दू बाहुल्य उत्तरी राज्यों को दोषी ठहराया जाता रहा है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले हिजाब (बुरखा) को लेकर यह विवाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा हिजाब नही है, इसलिए सभी धर्म के छात्र-छात्राओं को स्कूल की यूनीफार्म पहनना जरूरी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से देश के एक धर्म विशेष के अनुयायियों में उबाल सा आ गया है और इस टिप्पणी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का द्वार भी खटखटाया गया है।

इस विवाद को लेकर मुख्यतः तीन सवाल हवा में लहराये गए, पहला- क्या ईस्लाम में हिजाब पहनना आवश्यक बताया गया है। दूसरा- क्या स्कूल व कॉलेजों में यूनीफार्म पहनना जरूरी होने से मौलिक अधिकारों पर हमला हुआ है और तीसरा- कर्नाटक कोर्ट ने पांच फरवरी को जो फैसला सुनाया था संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है? इन सवालों पर कोर्ट का जवाब था कि ईस्लाम में हिजाब पहनने को जरूरी नहीं बताया गया है और वह आवश्यक प्रथा नही है, दूसरे सवाल के जवाब में कोर्ट ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में ''डेसकोड'' लागू करना गलत नही है और इस पर छात्र-छात्राएं अपनी नही कर सकते, तीसरे सवाल के जवाब में कोर्ट का कहना है कि सरकार के पास आदेश देने का अधिकार है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ चैन्नई से खिलाफत शुरू हुई और छात्राओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। यही नहीं छात्राओं ने इस फैसले के बाद राज्य के एक प्रमुख कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब को अहमियत देते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इस फैसले पर विवाद इतना बढ़ गया कि इस पर जम्मू-कश्मीर से चैन्नई तक बवाल खड़ा हो गया, कश्मीरी घुरविरोधी नेता मेहबूबा मुती और उमर अब्दुल्ला इस मसले पर एक साल खड़े नजर आए, वही वरिष्ठ मुस्लिम नेता असदुदीन औबेसी ने भी विरोधी स्वर अख्तियार किया जबकि महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य ने कोर्ट को इस टिप्पणी को स्वागत योग्य माना, सुश्री शाहिस्ता अम्बर ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं के नियम सभी के लिए बाध्यकारी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि इस हिजाब विवाद को कोई तो हवा दे रहा है? सामाजिक समरसता खत्म करने और अशांति पैदा करने की गरज से ऐसा किया जा रहा है।

इसी हिजाब विवाद के बीच एक अहम् सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि आज तो कॉलेज स्कूल की लड़कियां घुटने से फटी पैंट पहन शिक्षण संस्थाओं में जाती है, यही नहीं अब तो इसे फैशन में शुमार कर लिया गया है, फिर ऐसे माहौल में हिजाब को लेकर इतना विवाद क्यों? वैसे भी हमारे संविधान में खाने-पहनने और अपने तरीके से जीवन बसर करने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है और फिर इसी स्वतंत्रता के तहत यदि कोई अपना सौन्दर्य सार्वजनिक नहीं करना चाहता है और हिजाब पहना जाता है तो फिर इस पर आपत्ती का सवाल ही कहां पैदा होता है, किंतु यदि आप किसी शिक्षण संस्थान के छात्र है और वहां अध्ययन जारी रखना चाहते है तो फिर उक्त शिक्षण संस्थान के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये शिक्षण संस्थाएं किसी धर्म विशेष की न होकर सरकार की होती है और सरकारी संस्थानों में धर्म सम्बंधी भेदभाव नहीं किया जाता। कर्नाटक हाई कोर्ट की भी अपने फैसले में यही भावना निहित है।

पर पता नहीं, आज-कल तो हर मामले में राजनीति का प्रवेश पहले होता है, इसी कारण से कहा जा रहा है कि- ''अब घट-घट में भगवान नहीं, बल्कि उनकी जगह राजनीति ने ले ली हैं''। हिजाब काण्ड के साथ ही इस बात का दूसरा उदाहरण कश्मीर पर आई फिल्म ''द कश्मीर फाईल्स'' है, जिसके रिलीज होते ही राजनीति शुरू हो गई, जिसके प्रथम सूत्रधार माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी रहे, उन्हें इस फिल्म को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कोसने का मौका जो मिल गया, जबकि कश्मीरी पण्डितों का निर्दयतापूर्ण निष्कासन केन्द्र में आरूढ़ भाजपा सरकार के दौरान ही हुआ था, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस कटु सत्य को भुला देना कहां तक उचित है?

खैर, जो भी हो, किंतु आज विभिन्न मसलों को लेकर जिस तरह का जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है, क्या वह देशहित में है? इस गंभीर प्रश्न का गहन चिंतन कर जवाब खोजना चाहिये। (लेखक-ओमप्रकाश मेहता / ईएमएस)

शब्द पहेली - 7231

बाएँ से दाएँ

1. शमशीर, कृपाण-4
4. उपद्रवी, आतंकी-4
6. अनुबंध, संधि-3
8. धोखा, छल, मक्कारी-3
9. चांदी-3
11. अश्रु-2
13. नीचता-5
15. कुंजी, जिससे ताला खोलते हैं-2
16. पुराना जुकाम-3
18. प्रश्न-3
19. चांदी-3
20. जहां ताजिये दफन किए जाते हैं-4
22. बोरिया-बिस्तर-4

ऊपर से नीचे

1. झगड़ा, कहासुनी-4
2. संगीत यंत्र-2
3. बहुत बड़ा, विशाल-3
4. अपनत्व, अपनापा-5
5. अनबन, झगड़ा-4
7. कपड़े धोनेवाला-3
10. तहजीबदार-5
12. अकस्मात, सहसा-4
14. दृष्टि, निगाह-3
17. बेमिसाल, अनूठा-4
18. बलवान-3
21. उम्मीद, आशा-2

शब्द पहेली -7230 का हल

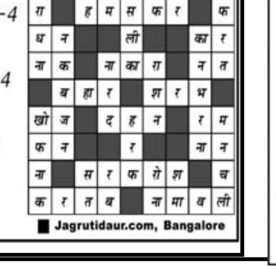

Jagrutidaur.com, Bangalore

शीघ्र-सहज न्याय का मंदिर है उपभोक्ता आयोग!

प्रायः न्यायालयो में तारीख पर तारीख दी जाती है,जिसकारण वादकारियों की चप्पलें तक घिस जाती है।दीवानी न्यायालय के बारे में तो कहावत है कि दावा दादा करता है तो न्याय पोते को मिलता है।इस मिथक को तोड़ने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।हालांकि यह काम यानि तारीख पर तारीख न देकर शीघ्र सहज न्याय देने का काम देश की उपभोक्ता अदालते,जो अब आयोग के रूप में परिवर्तित होकर उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय उपलब्ध करा रही है।हम कह सकते है, समय के साथ उपभोक्ताओ की सोच में भी अब बदलाव आया है।अब खरीदी गई वस्तु के खराब निकलने पर सिर्फ अफसोस व्यक्त करके उपभोक्ता घर नही बैठता, बल्कि दुकानदार से शिकायत करने के साथ ही खराब वस्तु को बदलवाने के लिए उपभोक्ता आयोग तक का दरवाजा खटखटाता है।इसी प्रकार खरीदी गई किसी सेवा में कमी मिलने पर उपभोक्ता अपने साथ हुए अन्याय के लिए प्रतिवाद करने लगा है और विभिन्न मंचो पर न्याय के लिए जाने लगा है।

उपभोक्ता के साथ कोई भी ठगी या सेवा में कमी न कर पाए,उपभोक्ता को कोई धोखा न दे सके ,कोई दुकानदार या सेवा प्रदाता झूठी सच्ची बाते करके किसी को खराब गुणवत्ता का सामान न बेच सके और किसी को खराब सेवा न दे सके । इसके लिए सभी को जागरूक रहना आवश्यक है। उपभोक्ता आयोग एक ऐसा न्याय का मंदिर है जहां आप सुगमता से न्याय मांग सकते है।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2019 की अधिसूचना भारत सरकार ने 15 जुलाई 2020 को जारी कर दी थी।जिसके तहत 20 जुलाई सन 2020 से उक्त संशोधित कानून प्रभावी हो गया था। इस बदले कानून से उपभोक्ताओं को शोषण और अन्याय से मुक्ति मिल रही है। इस कानून में किये गए बदलाव से उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के क्षेत्र में नई पहल का सूत्रपात हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण संशोधित कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता कही से भी उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस कानून में उपभोक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए साथ ही पुराने नियमों में सुधार की कोशिश भी की गई है।

जैसे सेंट्रल रेगुलेटर का गठन, भ्रामक विज्ञापनों पर भारी दंड और ई-कॉमर्स फर्मों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचने वाली कंपनियों के लिए सख्तक दिशानिर्देश इस नये कानून में शामिल किये गए हैं।उपभोक्ता अब कहीं से भी यानि जहां वह निवास करता है या जहां से उसने सामान या सेवा खरीदी है ,में से कही से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें गठित हैं जिन्हें आयोग के रूप मान्यता दी गई है।नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के क्षेत्राधिकार में बदलाव किया गया है। राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालतों के मुकाबले जिला अदालतों तक पहुंच ज्यादा होती है। इसलिए अब जिला उपभोक्ता अदालतें 50 लाख रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकेंगी।पहले जिला आयोग को एक करोड़ रुपये मूल्य के वादों की सुनवाई का अधिकार था,जो अब घटाकर 50 लाख रुपये तक किया गया है।

अब उपभोक्ता अपनी शिकायत कही से भी दर्ज कर सकता है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था, जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है या फिर उसकी कोई शाखा या कार्यालय जहां मौजूद है। ई-कॉमर्स अर्थात ऑन लाइन से बढ़ती खरीदारी को देखते हुए यह उपभोक्ताओं के हित मे यह एक अच्छा कदम है। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शिरकत करने की इजाजत दी गई है। इससे उपभोक्ता का पैसा और समय दोनों बच सकेंगे और उसे न्याय भी जल्दी मिल सकेगा। उपभोक्ता कानून के इतिहास का अवलोकन करें तो पता चलता है कि सन 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई थी और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। भारत मे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता आंदोलन का यह प्रथम प्रयास कहा जा सकता है।वही स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई।समय के साथ अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आन्दोलन देश मे आगे बढ़ता रहा और सन 24 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और जो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम में बाद में सन 1993 ,सन 2002 व अब 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन व्यापक संशोधनों के बाद यह एक सरल व सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित उपभोक्ता अदालतों के आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 72 के अधीन कारावास व दण्ड का प्रावधान किया गया है।

नए कानून में उत्पाद व विक्रेता कंपनी की जवाबदेही तय की गई है ।उत्पाद में निर्माण त्रुटि या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो उसे बनाने वाली कंपनी को हर्जाना देना होगा. यानि निर्माण त्रुटि में खराबी के कारण प्रेशर कुकर के फटने पर उपभोक्ता को चोट पहुंचती है तो उस हादसे के लिए कंपनी को हर्जाना देना होगा। पहले उपभोक्ता को केवल कुकर की लागत मिलती थी। उपभोक्ताओं को क्षति पूर्ति के लिए भी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था।जिससे मामले के निपटारे में सालों साल लग जाते थे।पहले कंपनियां अनैतिक तरीके से कोर्ट से तारीख पर तारीख ले लेती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उपभोक्ताओं को 90 दिन की समय सीमा में न्याय मिल जाना चाहिए।हालांकि इसमें प्रायः थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है।पहले जहां से उपभोक्ता ने सामान खरीदा था, वहीं के उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करना होता था। अब उपभोक्ता कहीं से भी सामान खरीदा हो, यदि उसमें खराबी है तो उसकी शिकायत घर या काम की जगह के आसपास के उपभोक्ता अदालत में कर सकता है। इस नये कानून का सबसे ज्यादा असर ई-कॉमर्स बिजनेस के क्षेत्र में होगा।अब इसके दायरे में सेवा प्रदाता भी आ जाएंगे. ठउत्पाद की जवाबदेही अब निर्माता के साथ सेवा प्रदाता और विक्रेताओं पर भी होगी. इसका अर्थ यह हुआ कि ई-कॉमर्स साइट खुद को एग्रीगेटर बताकर पल्ला नहीं झाड़ सकती हैं.ठई-कॉमर्स कंपनियों पर सीधे बिक्री पर लागू सभी कानून प्रभावी होंगे. अब अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे व्यापारिक मंच को विक्रेताओं के ब्योरे का खुलासा करना होगा. इनमें उनका पता, वेबसाइट, ई-मेल इत्यादि शामिल करना जरूरी हैं.ई-कॉमर्स फर्मों की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर किसी तरह के नकली उत्पादों की बिक्री न हो. अगर ऐसा होता है तो कंपनी पर दंड लग सकता है, क्योंकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर नकली उत्पादों की बिक्री के मामलो की शिकायतें मिलती रही हैं।

कानून में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) नाम का केंद्रीय रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है।यह उपभोक्ता के अधिकारों, अनुचित व्यापार व्यवहार, भ्रामक विज्ञापन और नकली उत्पादों की बिक्री से जुड़े मामलो को देखेगा और जरूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। उपभोक्तता संरक्षण अधिनियम 2019के पारित हो जाने के बाद कंपनियों पर इस बात की ज़िम्मेदारी अब और ज़्यादा होगी कि उनके उत्पादों के विज्ञापन भ्रामक न हों और उनके उत्पाद दावों के अनुरुप ही हों।वही नई विधिक व्यवस्था में राज्य उपभोक्ता आयोग की आर्थिक शक्ति थोड़ा कम की गई है।पहले राज्य आयोग को 10 करोड़ रुपये मूल्य तक की उपभोक्ता शिकायत सुनने की शक्ति थी,जिसे घटाकर 2 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। (लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन /ईएमएस)

(व्यंग्य) बुरा मानकर भी कर क्या लोगे !

बुरा न मानो होली है कहकर, बुरा मानने लायक कई वारदातें हमारे आपके साथ घट गईं। होली हो ली। सबको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिये कि बुरा मानकर भी हम सिवाय अपने किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बुरा तो लगता है जब धार्मिक स्थल राजनैतिक फतवे जारी करने के केंद्र बनते दिखते हैं। अच्छा नहीं लगता जब सप्ताह के दिन विशेष भरी दोपहर पूजा इबादत के लिये इकट्ठे हुये लोग राजनैतिक मंथन करते नजर आते हैं। बुरा लगता है जब सोशल मीडीया की ताकत का उपयोग भोली भीड़ को गुमराह करने में होता दिखता है। बुरा लगता है जब काले कपड़े में लड़कियों को गठरी बनाने की साजिश होती समझ आती है। बुरा लगता है जब भैंस के आगे बीन बजाते रहने पर भी भैंस खड़ी पगुराती ही रह जाती है। बुरा लगता है जब मंच से चीख चीख कर भीड़ को वास्तविकता समझाने की हर कोशिश परिणामों में बेकार हो जाती है। इसलिये राग गर्दभ में सुर से सुर मिलाने में ही भलाई है। यही लोकतंत्र है। जो राग गर्दभ में आलाप मिलायेंगे, ताल बैठायेंगे, भैया जी ! वे ही नवाजे जायेंगे। जो सही धुन बताने के लिये अपनी ढ़पली का अपना अलग राग बजाने की कोशिश करेंगे, भीड़ उन्हें दरकिनारे कर देगी। भीड़ के चेहरे रंगे पुते होते हैं। भीड़ के चेहरों के नाम नहीं होते। भीड़ जिससे भिड़ जाये उसका हारना तय है। लोकतंत्र में भीड़ के पास वोट होते हैं और वोट के बूते ही सत्ता होती है। सत्ता वही करती है जो भीड़ चाहती है। भीड़ सड़क जाम कर सकती है, भीड़ थियेटर में जयकारा लगा सकती है, भीड़ मारपीट, गाली गलौज, कुछ भी कर सकती है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन और मुफ्तखोरी के लुभावने वादों से भीड़ खरीदना लोकतांत्रिक कला है। बेरोजगारी भत्ते, मातृत्व भत्ते, कुपोषण भत्ते, उम्रदराज होने पर वरिष्ठता भत्ते जैसे आकर्षक शब्दों के बैनरों से बनी योजनाओ से बिन मेहनत कमाई के जनोन्मुखी कार्यक्रम भीड़ को वोट बैंक बनाये रखते हैं। भीड़ बिकती समझ आती है पर बुरा मानकर भी कर क्या लोगे ! खरीदने बिकने के सिलसिले मन ही मन समझने के लिये होते हैं, बुरा भला मानने के लिये नहीं। खिलाड़ियो को नीलामी में बड़ी बड़ी कीमतों पर सरे आम खरीद कर, एक रंग की पोषाक की लीग टीमें बनाई जाती हैं। मैच होते हैं, भीड़ का काम बिके हुये खिलाड़ियों को चीयर करना होता है। चीयर गर्ल्स भीड़ का मनोरंजन करती हैं। भीड़ में शामिल हर चेहरा व्यवस्था की इकाई होता है। ये चेहरे सट्टा लगाते है, हार जीत होती है करोड़ो के वारे न्यारे होते हैं। बुद्धिमान भीड़ को हांकते हैं। जैसे चरवाहा भेड़ों को हांकता है। भीड़ को भेड़ चाल पसंद होती है। भीड़ तालियां पीटकर समर्थन करती है। काले झंडे दिखाकर, टमाटर फेंककर और हूट करके भीड़ विरोध जताती है। आग लगाकर, तोड़ फोड़ करके भीड़ गुम हो जाती है। भीड़ को कही गई कड़वी बात भी किसी के लिये व्यक्तिगत नहीं होती। भीड़ उन्मादी होती है। भीड़ के उन्माद को दिशा देने वाला जननायक बन जाता है। भीड़ के कारनामों का बुरा नहीं मानना चाहिये, बल्कि किसी पुरातन संदर्भ से गलत सही तरीके से उसे जोड़कर सही साबित कर देने में ही वाहवाही होती है। भीड़ प्रसन्न तो सब अमन चैन। सो बुरा न मानो, होली है, और जो बुरा मान भी जाओगे तो कुछ कर न सकोगे क्योंकि तुम भीड़ नही हो, और अकेला चना भाड़ नही फोड़ सकता। इसलिये भीड़ भाड़ में बने रहो, मन लगा रहेगा। (लेखक- विवेक रंजन श्रीवास्तव/ईएमएस)

आज का इतिहास 21 मार्च

1779 अंग्रजों ने टीपू सुल्तान से बेंगलोर छीना.

1801 सिकंदरिया मे ब्रिटिश फौजों ने फ्रांसीसी फौजों को शिकस्त दी.

1821 स्पेन मे भूकम्प से छह हजार से अधिक लोग मरे.

1831 आस्ट्रियाई फौजें इटली में विद्रोह का दमन करने पहुँची.

1836 पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कलकत्ता में खुला .

1884 फ्रांस मे श्रमिक संघों को वैधता प्रदान की गई.

1905 ब्रिटेन व फ्रांस ने रूस के खिलाफ एक समझौता किया.

1921 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज स्वीकार किया गया.

1939 जर्मनी ने लिथुआनिया से मेमेल अपने अधिकार मे ले लिया.

1960 दक्षिण अफ्रीका के शार्यविले में सत्तावन लोग मारे गये और आपातकालीन की घोषणा कर दी गई.

1977 आपात स्थिति को वापस ले ली गई.

1977 श्रीमति इन्दिरा गाँधी ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया.

1992 पनडुब्बी'शंकुल'का जलावतरण.

1996 भारतीय उपग्रह आई.आर.एस.-पी3 का श्रीहरिकोटा का सफल परीक्षण.

1999 सऊदी अरब का परिवहन विमान में दुर्घटनाग्रस्त जिसमें 98 लोग मारे गए.

2000 उग्रवादियों ने दक्षिण कश्मीर में 35 सिक्खों की हत्या कर दी.

दैनिक पंचांग

21 मार्च 2022 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	मीन में	मीन	05.45 बजे से
चंद्र	तुला में	मेष	07.19 बजे से
मंगल	मकर में	वृष	08.59 बजे से
बुध	कुंभ में	मिथुन	10.57 बजे से
गुरु	कुंभ में	कर्क	13.11 बजे से
शुक्र	मकर में	सिंह	15.27 बजे से
शनि	मकर में	कन्या	17.39 बजे से
राहु	वृष में	तुला	19.49 बजे से
केतु	वृश्चिक में	वृश्चिक	22.04 ब.से
राहुकाल	7.30 से 9.00 बजे तक	धनु	00.20 बजे से
		मकर	02.25 बजे से
		कुंभ	04.12 बजे से

सोमवार 2022 वर्ष का 80 वां दिन **दिशाशूल** पूर्व **ऋतु** बसंत। **विक्रम संवत्** 2078 **शक संवत्** 1943 **मास** चैत्र (दक्षिण भारत में फाल्गुन) **पक्ष** कृष्ण **तिथि** तृतीया 08.21 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** स्वाती 21.31 बजे को समाप्त। **योग** व्याघात 15.54 बजे को समाप्त। **करण** विष्टि 08.21 बजे तदनन्तर बव 19.24 बजे को समाप्त। **चन्द्रायु** 18.3 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 00° 08' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1871194 **जूलियन दिन** 2459659.5 **कलियुग संवत्** 5123 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2548 **हिजरी सन्** 1443 **महीना** सावान **तारीख** 17 **विशेष** संकष्टी चतुर्थी, विश्व वानिकी, ओशो संबोधि दिवस।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
अमृत	05.53 से	07.22 बजे तक	चर	05.43 से	07.14 बजे तक
काल	07.22 से	08.50 बजे तक	रोग	07.14 से	08.45 बजे तक
शुभ	08.50 से	10.19 बजे तक	काल	08.45 से	10.17 बजे तक
रोग	10.19 से	11.48 बजे तक	लाभ	10.17 से	11.48 बजे तक
उद्वेग	11.48 से	01.17 बजे तक	उद्वेग	11.48 से	01.19 बजे तक
चर	01.17 से	02.45 बजे तक	शुभ	01.19 से	02.51 बजे तक
लाभ	02.45 से	04.14 बजे तक	अमृत	02.51 से	04.2 बजे तक
अमृत	04.14 से	05.43 बजे तक	चर	04.22 से	05.53 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। Jagrutidaur.com, Bangalore

चीन का घातक हथियार किसी भी देश की सेटेलाइट को कर सकता है नष्ट

-इसे वेव बर्स्ट तकनीक पर आधारित या डायरेक्टक एनर्जी वेपंस कहा जाता है

ताइपे(ईएमएस)। चीन ने एक ऐसा घातक हथियार बनाया है, जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में मौजूद सेटेलाइट को निशाना बनाकर खत्मआ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के हथियार नहीं बने हैं। अब तक इसके लिए लान्गक रेंज मिसाइल के जरिए किया जाता रहा है। अब चीन के शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक ऐसी माइक्रोवेव मशीन जिसको रिलेटिविस्टिक एम्लीरेप फायर (आरकेए) का नाम दिया गया है, तैयार की है जो अंतरिक्ष में मौजूद सेटेलाइट्स की नाकाम करने और इसको खत्म करने की काबलियत रखता है।

ताइवान के न्यू(ज पेपर की जानकारी के मुताबिक चीन की ये मशीन वेव बर्स्टश तकनीक पर आधारित है और इन्हेंक या डायरेक्टज एनर्जी वेपंस कहा जाता है। जिसके केए बेंड से निकलने वाली पांच मेगावाट की वेव सेटेलाइट को नाकाम या नष्टस कर सकती है। इसके इलेक्ट्रो मैग्नेवटिक स्पेवक्ट्रेम को सिविल और मिलिट्री के इस्तैमाल के लिए कम या ज्याकदा भी किया जा सकता है। हाईवेव की तकनीक भी कोई नई नहीं है, लेकिन चीन की इस मशीन की बात करें तो ये सेटेलाइट पर निशाना जमीन से नहीं बल्कि आसमान से ही लगाएगी। साधारणा भाषा में कहे तो इसको सेटेलाइट में ही लगाया जाएगा और समय आने पर ये अंतरिक्ष में ही घूमते हुए दूसरी सेटेलाइट को निशाना बना सकेगी। इस मशीन से निकलने वाली घातक वेव किसी भी सेटेलाइट के अंदर लगे बेहद संसेटिव इलेक्ट्रा निक पार्ट्स को नष्ट कर देगी। इसकी वजह से सेटेलाइट निष्क्रेय हो जाएगी। इससे निकलने वाली इलेक्ट्रो मैग्नेकटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इतनी घातक होती है कि ये इलेक्ट्रो निक पार्ट्स को राख बना सकती है। हालांकि चीन ने इस तरह के वेपंस को डेवलेप करने की खबरों को गलत बताया है और कहा है कि उसने ऐसी किसी मशीन को नहीं बनाया है। ताइवान न्यूकज के मुताबिक यदि ये बात साबित हो जाती है तो चीन को विश्वो समुदाय की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ सकती है। एक समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है, जिसको युद्ध के लिए इस्तेरमाल नहीं किया जा सकता है। न कही युद्ध की सूरत में किसी सेटेलाइट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। विश्वट के कुछ बड़े देश जिस तरह से इस तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए भविष्यत में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

खेल - समाचार

आईसीसी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच को औसत से निचले स्तर का माना

दुबई (ईएमएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच को औसत से कम स्तर का मानते हुए एक नकारात्मक अंक दिया है। इस मैदान पर हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मैच में तीन दिन के अंदर ही परिणाम निकल गया था। भारतीय टीम ने दिन-रात्रि के इस मैच को 238 रन से जीता था। वहीं अब मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ ने मैदान की पिच को औसत से निचले स्तर का माना है। इसके लिए उसके एक नकारात्मक अंक भी दिया गया है। पांच 5 साल में अगर किसी पिच को 5 नकारात्मक अंक मिलते हैं तो उस पर एक साल का प्रतिबंध लग सकता है। इस दौरान यहां कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं हो सकता।

श्रीनाथ ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'पिच ने पहले ही दिन काफी टर्न लिया हालांकि हर सत्र में इसमें सुधार हुआ प मेरे विचार से यहां गेंद और बल्ले में मुकाबला बराबरी का नहीं रहा। ' आईसीसी के अनुसार पिच को मिले नकारात्मक अंक पां साल तक माने जाते हैं। ऐसे में 5 नकारात्मक अंक होने पर मैदान से मेजबानी वापस ली जा सकती है।

ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के सेमीफाइनल में हारीं गायत्री गोपीचंद और त्रिशा

बर्मिंघम (ईएमएस)। भारतीय बैडमिंटन टीम के राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद और उनकी जोड़ीदार त्रिशा जॉली ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में हार के साथ ही बाहर हो गयी हैं। महिला युगम मुकाबले में गायत्री और त्रिशा की जोड़ी को शु जियान झांग और यु झेंग की जोड़ी ने सीधे गेमों में 17-21, 16-21 से हराया। यह मुकाबला बेहद संघर्षपूण रहा। गायत्री और उनकी जोड़ीदार त्रिशा ने इससे पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर एक नया रिकार्ड अपने नाम किया था।

गायत्री और त्रिशा ने क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 2 कोरियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया था। यह पहला अवसर है जब भारतीय महिलाओं ने इस टूर्नामेंट के महिला युगल के अंतिम-4 में जगह बनायी।

महिला विश्वकप : इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक विकेट से हराया

आकलैंड (ईएमएस)। इंग्लैंड ने यहां आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के लीग चरण के रोमांचक मुकाबले में मेजबान न्यूजीलैंड को एक विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मैडी ग्रीन के नाबाद 52 रनों ओर कप्तान सोफी डेविन के 41 रनों की सहायता से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाये। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज केट क्रास ने 35 रन देकर तीन विकेट लिए। वहीं स्पिनर सोफी एक्सेलस्टोन ने 41 रन देकर तीन विकेट जिए जबकि स्पिनर चार्ली डीन ने 36 रन देकर दो विकेट लिए। इस प्रकार इंग्लैंड को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य मिला जो उसने नौ विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान हीथर नाइट ने 53 जबकि सोफी डंकले ने 33 रन बनाये , ऑलराउंडर नटाली स्किवर ने 61 रन बनाये।इसके बाद आन्या श्रबसोल ने 07 और चार्ली डीन शून्य ने इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचाया जिससे टीम ने टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत से इंग्लैंड की टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। उसने पांचवें स्थान से न्यूजीलैंड को हटा दिया है। भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सभी के चार अंक हैं। भारत और इंग्लैंड के दो मैच बचे हैं जबकि न्यूजीलैंड का सिर्फ एक मैच बाकी है।

इस मैच में टॉस जीत कर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही। पहले विकेट के लिए उसने 61 रन बनाये। सूजी बेटस ने 22 और सोफी डियाने ने 42 रन बनाये। इनके आउट होने के बाद अमेलिया केर ने 24 जबकि हालांकि डेविन को 15वें ओवर में पीठ में दर्द के बाद रिटायर होना पड़ा।

इसके बाद एम सैटर्थवेट (24) और ग्रीन ने अच्छी बल्लेबाजी की। इंग्लैंड ने क्षेत्ररक्षण में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दो खिलाड़ियों को रन आउट कर दिया। सैटर्थवेट को डीन ने पगबाधा आउट किया और फिर क्रास और एक्सेलस्टोन ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर न्यूजीलैंड को समेट दिया।

इंग्लैंड के गेंदबाजों का प्रदर्शन इस मैच में अच्छा रहा जिससे उसने कीवी बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज डैनी वाट 12 बनाकर ही आउट हो गयीं। टैमी ब्यूमोंट 25 रनों पर पेवेलियन लौट गयीं। इसके बाद नाइट ने 53 गेंद में 42 रन बनाये लेकिन वह 23वें ओवर में फ्रैंकी मैके की गेंद पर पगबाधा आउट हो गईं। विकेटकीपर एमी जोंस भी एक रन बना पायीं। स्किवर ने फिर डंकले 33 के साथ मिलकर 70 रन की साझे दारी कर टीम को वापसी करायी।

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ब्रैथवेट ने बनाया रिकार्ड

एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी बने

ब्रिजटाउन (ईएमएस)। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अपनी 160 रनों की शतकीय पारी से अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने के साथ ही एक अहम रिकार्ड भी अपने नाम किया है। ब्रैथवेट ने 160 जबकि जर्मेन ब्लैकवुड ने 102 रनों की शतकीय पारी खेलकर वेस्टइंडीज को पहली पारी में 411 रनों तक पहुंचाया। इसी के साथ ही चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम ने बिना किसी नुकसान के 50 रन बना लिए थे। एलेक्स लीस 18 और जैक क्राउले 21 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 507 रन बनाये थे। इस प्रकार उसके पा अब कुल बढ़त 136 रनों हो गई है।

चौथे दिन के खेल में ब्रेथवेट ने 489 गेंदें खेलने के साथ ही एक अहम रिकॉर्ड बनाया। अब वह पूर्व कप्तान ब्रायन लारा के साल 2004 में 582 गेंद खेलने के रिकार्ड के बाद एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गये हैं। उन्होंने कार्ल हूपर 402 गेंद , क्रिस गेल 396 गेंद और जिम्मी एडम्स 372 गेंद के रिकार्ड को पीछे छोड़ा। ब्रेथवेट और ब्लैकवुड के अलावा वेस्टइंडीज के विकेटकीपर बल्लेबाज जोशुआ डि सिल्वा ने भी अच्छी पारी खेली। उन्होंने 112 गेंदों पर 33 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की ओर से जैक लीच ने तीन जबकि साकिब महमूद और बेन स्टोक्स ने दो-दो और क्रिस वोक्स, फिशर और डेनियल लॉरेंस को एक-एक विकेट मिला।

भवानी देवी फेंसिंग विश्व कप में 23वें स्थान पर रहीं

तुर्की (ईएमएस)। भारत की भवानी देवी यहां फेंसिंग (तलवार बाजी) विश्व कप में शीर्ष 25 खिलाड़ियों में रही हैं। ओलंपिक में शामिल रही एकमात्र भारतीय तलवार बाज भवानी विश्व के 166 फेंसर्स में 23वें स्थान पर रहीं। भवानी को महिला व्यक्तिगत सेबर राउंड-32 में फ्रांस की कैरोलिन क्वेरोली के हाथों 9-15 से हार का सामना करना पड़ा। वह ग्रुप चरण में एक भी मैच नहीं हारीं रहीं और इस कारण उन्हें राउंड-64 में प्रवेश मिला। राउंड-64 में उन्होंने चीनी तलवारबाज लिन केसी को 15-8 से हराया पर राउंड-32 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस कारण इस भारतीय खिलाड़ी के हाथों से मैच निकल गया।

एफआईएच प्रो लीग हॉकी में भारतीय टीम को अर्जेंटीना ने 3-1 से हराया

भुवनेश्वर (ईएमएस)। एफआईएच प्रो हॉकी लीग में भारतीय टीम को मेहमान टीम अर्जेंटीना के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। अर्जेंटीना ने भारतीय टीम को शूटआउट में 3-1 से हराया। इस मैच में तय समय तक स्कोर 2-2 से बराबर था पर शूटआउट में भारतीय टीम पिछड़ गयी। पहले क्वार्टर में भारतीय टीम हॉवी रही गुरजंत सिंह ने 38वें मिनट में एक गोल कर भारतीय टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद अर्जेंटीना की ओर से निकोलस एकोस्टा ने 45 वें मिनट में गोल दागकर स्कोर बराबरी पर ला दिया। निकोलस कीनन ने 52वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 2-1 से बढ़त दिला। भारतीय टीम की ओर से मनदीप सिंह ने 60वें मिनट में गोल कर फिर स्कोर बराबरी पर ला दिया। तय समय तक दोनो ही टीमों के बराबरी पर रहने से मुकाबला पैनाल्टी शूटआउट में चला गया। यहां भारतीय खिलाड़ी नाकाम रहे। केवल हरमनप्रीत सिंह ही गोल कर सके जबकि अभिषेक, गुरजंत और सुखजीत सिंह गोल नहीं कर पाये।

वहीं अर्जेंटीना की ओर से कीनन, टॉमस डोमेने और लुकास टोस्कानी ने गोल किये। इस जीत से अर्जेंटीना को एक बोनस अंक भी मिला है। इस प्रकार टीम पांच मैचों में 11 अंक लेकर चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, भारतीय टीम 7 मैचों में 13 अंक लेकर दूसरे स्थान पर बरकरार है।

फ्रेंच फुटबॉल लीग मुकाबले से बाहर रहेंगे मेसी

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी बीमार होने के कारण फ्रेंच फुटबॉल लीग मुकाबले में नहीं खेलेंगे। फ्रेंच फुटबॉल लीग के मुकाबले मोनाको में खेले जाएंगे। पिछले साल पीएसजी से जुड़े मेसी फ्रेंच लीग के पहले सत्र में संघर्ष करते नजर आये थे। मोनाको के मुकाबले से पहले मेसी ने सभी प्रतियोगिताओं में 26 मैचों में केवल सात गोल ही किए थे। वहीं पिछले सत्र में बार्सिलोना के साथ उन्होंने 38 गोल किए थे।

पूर्व दिशा की ओर विस्तार नहीं करने का वायदा निभाए नाटो : चीन

बीजिंग (ईएमएस)। यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर सख्त पाबंदियों से चीन भड़क गया है। उसने नाटो के विस्तार का मुखर विरोध किया है। नाटो ने वादा किया है कि वह पूर्व दिशा की ओर विस्तार नहीं करेगा। चीनी राजनयिक ने कहा कि नाटो को अपने वायदे पर कायम रहना चाहिए। चीन के उप विदेशमंत्री ली युचेंग ने शनिवार को दिए भाषण में यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर सख्त पाबंदियों की आलोचना करते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध की जड़ में शीतयुद्ध की मानसिकता और दुनिया में एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन कायम करने की राजनीति है।

क्रेमलिन (रूसी सरकार का मुख्यालय) के रुख का समर्थन करते हुए चीनी राजनयिक ने कहा अगर नाटो का विस्तार और होगा तो यह मॉस्को के करीब पहुंच जाएगा जहां से मिसाइल पांच से सात मिनट में क्रेमलिन को निशाना बना सकती है। उन्होंने आगाह किया कि एक परमाणु संपन्न प्रमुख देश को हाशिए पर धकेलने का परिणाम कितना भयानक होगा इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।

उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बार-बार दोहराए गए रुख का समर्थन करते हुए कहा कि नाटो को विघटित करना चाहिए था और वॉरसा संधि के साथ इतिहास में भेजना चाहिए था। चीनी राजनयिक ने कहा नाटो को विखंडित करने के बजाय विस्तार दिया जा रहा है। नाटो ने युगोस्लाविया, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया।

युचेंग ने कहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से बातचीत में यूक्रेन के पक्षों को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने और चल रहे संवाद और वार्ता को जारी रखने' का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और नाटो को भी रूस से संवाद करना चाहिए ताकि यूक्रेन संकट का समाधान निकाला जा सके और रूस और यूक्रेन दोनों की सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सके।

820 करोड़ की वसूली के लिए 12 एनपीए खाते एआरसी को बेचेगा एसबीआई

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 820 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए 12 एनपीए खाते एआरसी को बेचेगा। एसबीआई ने अपनी अधिसूचना में कहा कि वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप उसने इन एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियां) खातों को संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी)/ बैंकों/ एनबीएफसी/ वित्तीय संस्थानों को बेचने की पेशकश की है।

एसबीआई ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न नोटिसों में इस महीने से 13 अप्रैल तक कुल 12 एनपीए को बिक्री के लिए रखा है। एसबीआई ने कहा कि इनमें सबसे बड़ा एनपीए खाता ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड का 396.74 करोड़ रुपए का है, जिसे 85 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ 29 मार्च, 2022 को होने वाली ई-नीलामी में बेचा जाएगा। इसके अलावा बालासोर अलॉयज के एक खाते की भी 29 मार्च को ई-नीलामी की जाएगी। यह एनपीए खाता 186.10 करोड़ रुपये (आरक्षित मूल्य 178.22 करोड़ रुपये) का है। बैंक 30 मार्च को कुल 112.05 करोड़ रुपये के छह खातों की ई-नीलामी करेगा। एसबीआई शेष चार एनपीए खातों की नीलामी 13 अप्रैल को करेगा, जिसका कुल बकाया 125.32 करोड़ रुपए है।

फ्यूचर समूह की कंपनियों की अप्रैल में होगी शेयरधारकों और लेनदारों की बैठक

नई दिल्ली (ईएमएस)। किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर बाजारों को बताया कि वे रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी देने के लिए अपने संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों की बैठक 20 और 21 अप्रैल को बुलाएंगी। फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड और फ्यूचर सप्लाई चेन सहित समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयरधारकों और लेनदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली बैठकों की तारीखों और अन्य प्रक्रियाओं के बारे में शेयर बाजारों को बताया। इन कंपनियों ने बताया कि ये बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य ध्वनि-दृश्य माध्यमों के जरिए आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा 28 फरवरी को पारित आदेश के मुताबिक शेयरधारकों की बैठक 20 अप्रैल 2022 को होगी और इसके अगले दिन 21 अप्रैल को लेनदारों की मंजूरी लेने के लिए बैठक होगी। एनसीएलटी ने इस सौदे का विरोध करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की अर्जी को भी ठुकरा दिया था। अमेजन इस सौदे को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती रही है। रिलायंस के साथ अगस्त 2020 में हुए सौदे के तहत फ्यूचर समूह की 19 कंपनियों को एक साथ मिलाकर एक कंपनी बनाई जाएगी और फिर उसे रिलायंस रिटेल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

सौर उपकरण विनिर्माताओं को 30 प्रतिशत क्षमता पर करना पड़ रहा परिचालन

- अखिल भारतीय सौर उद्योग संघ ने बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को बताई समस्या

नई दिल्ली (ईएमएस)। सौर उपकरण विनिर्माताओं को अभी अपने संयंत्रों का परिचालन मात्र 30 प्रतिशत क्षमता पर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। अखिल भारतीय सौर उद्योग संघ (एआईएसआईए) ने बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को अपनी स्थिति से अवगत कराया है। संघ का कहना है कि घरेलू विनिर्माताओं को अपनी पकड़ बनाने तथा स्थापित होने में मदद के लिए संरचनात्मक रक्षोपायों के साथ शुल्क अड़चनों को भी दूर करने की जरूरत है। इससे पहले इसी सप्ताह सिंह को लिखे पत्र में संघ ने कहा कि हम पिछले एक दशक से पुनरोद्धार की उम्मीद कर रहे हैं। कड़ी चुनौतियों के बीच आज हमारा टिके रहना मुश्किल हो गया है। एक मजबूत मेक इन इंडिया सौर विनिर्माण के बिना देश की ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा पर आशंका मंडराती रहेगी। पत्र में कहा गया है कि घरेलू उपकरण विनिर्माताओं को स्थापित करने के लिए संरचनात्मक रक्षोपाय जरूरी है। विनिर्माताओं को कम से कम चार से पांच साल सीमा शुल्क, रक्षोपाय या सेफगार्ड शुल्क के मोर्चे पर मदद दी जानी चाहिए और उसके बाद इन्हें धीरे-धीरे वापस लिया जाना चाहिए।

विनिर्माताओं ने कहा कि अप्रैल, 2021 से सौर उपकरणों का आयात मासिक आधार पर लगातार 800 मेगावॉट से ऊपर बना हुआ है। फरवरी, 2022 तक 11 माह में कुल आयात 16 गीगावॉट है। यह कुल 10 गीगावॉट की स्थापना से कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि बड़ी मात्रा में भंडार जमा हो रहा है। सितंबर, 2021 से फरवरी, 2022 तक छह माह के दौरान मॉड्यूल का आयात 11.93 गीगावॉट रहा। इससे पता चलता है कि डेवलपर्स और व्यापारी घरेलू विनिर्माण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संघ ने कहा कि फरवरी, 2022 में 3.21 गीगावॉट के आयात से घरेलू विनिर्माताओं की स्थिति का पता चलता है।

आयकर विभाग में सुधार, अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकॉर्ड कर संग्रहः सीबीडीटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जेबी मोहपात्रा ने कहा कि सरकार के आयकर विभाग में सुधार और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के निणर्यों से रिकॉर्ड प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है। उन्होंने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था संबंधित आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। मोहपात्रा ने एक साक्षात्कार में कहा ?कि यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि अगले साल स्थिति कैसी होंगी लेकिन यह कहने के लिए कोई जगह नहीं है कि अच्छा समय केवल चार तिमाहियों तक रहता है। उन्होंने बातचीत के दौरान रिकॉर्ड कर संग्रह के कारणों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा ?कि सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी होगी, कर संग्रह उतना ही अच्छा होगा, जो अभी हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर संग्रह पर प्रभाव डालने वाले विभागों में किए गए सुधारों से भी संग्रह बढ़ा है। मोहपात्रा ने कहा कि ऐसे कई नीतिगत उपाय हैं, जो बजट में या बजट के बाहर उठाये गए हैं और अब इन उपायों का प्रभाव या लाभ अब दिख रहा है। उन्होंने कहा ?कि कर संग्रह में वृद्धि का तीसरा कारण विभाग के भीतर सुधार की दिशा में पिछले चार वर्ष से उठाए जा रहे कदम हो सकते हैं।

महापात्र ने कहा ?कि चौथा कारण छोटा लेकिन महत्वपूर्ण है और यह आयकर विभाग में प्रौद्योगिकी शामिल करने से संबंधित है। उन्होंने बताया कि 13.63 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर संग्रह (16 मार्च को) में से केवल 54,000-55,000 करोड़ रुपए ही नियमित निर्धारण कर से आया है। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा ?कि शेष संग्रह स्वैच्छिक अनुपालन के माध्यम से आ रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि करदाता उन्हें मिल रही वित्तीय जानकारी से सशक्त हो रहे हैं। सीबीडीटी दरअसल आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है।

फरवरी में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 248 करोड़ निकाले

नई दिल्ली (ईएमएस)। निवेशकों का रुझान अन्य विकल्पों की तुलना में शेयरों की ओर बढ़ने से फरवरी में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों (ईटीएफ) से 248 करोड़ रुपए की निकासी देखने को मिली है। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि गोल्ड ईटीएफ से निवेशकों ने निकासी की है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के अनुसार जनवरी में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 452 करोड़ रुपए निकाले थे। इससे पहले दिसंबर में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश 313 करोड़ रुपये रहा था। निकासी के बावजूद इस श्रेणी में प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) फरवरी के आ?खिर तक बढ़कर 18,727 करोड़ रुपए हो गईं, जो जनवरी के आ?खिर तक 17,839 करोड़ रुपए थीं। इस दौरान गोल्ड ईटीएफ में फोलियो की संख्या 3.09 लाख बढ़कर 37.74 लाख हो गई।

एलएक्सएमई की संस्थापक प्रीति राठी गुप्ता ने कहा कि यह रुख दर्शाता है कि स्वर्ण संपत्तियों को निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो के विविधीकरण और बाजार उतार-चढ़ाव में हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से निकासी संभवतः आकर्षक रिटर्न की वजह से अपने पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करने के लिए की है। मॉर्निंगस्टार इंडिया की वरिष्ठ विश्लेषक-प्रबंधक शोध कविता कृष्णन ने कहा कि निवेशक सोने को हमेशा ऐसी संपत्ति के रूप में तरजीह देते हैं जिसका इस्तेमाल जोखिम से बचाव और अपने निवेश के विविधीकरण के लिए किया जा सकता है।

आयकर विभाग ने पुणे व ठाणे के स्टार्टअप पर छापेमारी में सामने आई 224 करोड़ काले धन की जानकारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे के एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप समूह पर छापेमारी के बाद लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से रविवार को यह जानकारी दी गई। विभाग ने एक बयान में कहा कि छापेमारी की कार्रवाई नौ मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 23 परिसरों पर की गई।

यह समूह निर्माण सामग्री की थोक और खुदरा बिक्री का काम करता है और इसका सालाना 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार है। बयान के मुताबिक, यह पाया गया कि समूह ने खातों में फर्जी फर्जी खरीदारी दर्ज की। इसके अलावा समूह ने बेहिसाबी नकदी जमा की। सीबीडीटी ने कहा ये साक्ष्य सामने रखकर समूह के निदेशकों से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने विभिन्न आकलन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया। उन्होंने इसके बाद बकाया कर देनदारी के भुगतान की पेशकश की।

जांच में यह भी सामने आया कि समूह ने मॉरीशस मार्ग से काफी ऊंचे प्रीमियम पर शेयर जारी कर विदेशी कोष भी जुटाया। सीबीडीटी ने कहा कि मुंबई और ठाणे की मुखौटा कंपनियों के एक जटिल हवाला नेटवर्क का भी पता चला है।

पहले मिसाइलों से हमला, अब यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पा रही रूसी सेना

- मरने की कगार पर हजारों लोग

कीव (ईएमएस)। युद्ध के बीच घिरे यूक्रेन में बमबारी से बचने के लिए सैकड़ों लोग शहरों में छिपे हुए हैं। रूसी सेनाओं का जैसे-जैसे शहर में कब्जा बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इनकी ज्यादती की खबरें भी बढ़ रही हैं। मारियुपोल के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शहर में बच्चे, बुजुर्ग मर रहे हैं। शहर नष्ट हो गया है और इसे पृथ्वी के नक्शे से मिटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क सैन्य-नागरिक प्रशासन के प्रमुख पाव्लो क्यारिलेंको ने कहा कि हजारों मारियुपोल निवासी कब्जे वाले मानहुशी और मेलेकिन में भूख से मर रहे हैं। रूसी सेनाओं ने उन्हें भोजन, पानी और सुरक्षित मार्ग मुहैया करने से इनकार कर दिया है। मारियुपोल नगर परिषद ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने कई हजार लोगों को रूस की सीमा में जाने के लिए मजबूर किया है। परिषद ने कहा कि कब्जे वाले लोगों को यूक्रेन छोड़कर रूसी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कब्जा करने वालों ने अवैध रूप से लेवोबेरेज्नी जिले से लोगों को बाहर निकाला और एक स्पोर्ट्स क्लब की इमारत में शेल्डर बनाया है। ये वो लोग हैं, जो बमबारी से बचने के लिए छिपे हुए थे। शेल्डर में लोगों की हालत काफी खराब है। इन्हें भोजन-पानी जैसे मूलभूत चीजें भी नहीं मिल रही हैं।

दक्षिण-पूर्वी शहर मारियुपोल में शनिवार को रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच विशाल इस्पात संयंत्र पर कब्जा करने के लिए संघर्ष हुआ। यूक्रेन की प्रमुख औद्योगिक संस्थानों में से एक मारियुपोल स्थित अजोव स्टील प्लांट पर कब्जा को लेकर परस्पर विरोधी रिपोर्टें आ रही हैं। अजोव बटालियन के सदस्य व्लादस्लिाव सोबोलिवेस्की ने यूक्रेनी टेलीविजन को बताया, दुश्मन शहर में इतनी दूर नहीं पहुंचा है। यूक्रेनी नौसेना, आजोव बटालियन व पुलिस शहर और उसके नागरिकों की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि अजोव स्टील प्लांट हमारे नियंत्रण में है। प्लांट सहित पूरे शहर में हवाई हमले हुए, लेकिन दुश्मन हमारे प्लांट पर हाथ नहीं डाल पाए। रिपोर्ट के अनुसार विशाल स्टीलवर्क्स मारियुपोल शहर के मध्य के तुरंत बाद पूर्व में स्थित है। रूस के सुरक्षा बलों का इस संस्थान कब्जा होना यूक्रेनी प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका होगा।

आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं, स्कूली परीक्षा कैंसिल

कोलंबो (ईएमएस)। श्रीलंका इन दिनों भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में पेपर खरीदने के लिए डॉलर नहीं है। पेपर नहीं खरीद पाने के कारण देश में लाखों स्टूडेंट्स की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा कब तक होगी इसकी भी सूचना नहीं दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक बाहर से पेपर मंगाने के लिए देश के पास डॉलर नहीं है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से स्कूली छात्रों के लिए टर्म परीक्षा होने वाली थी लेकिन देश में पेपर की भारी कमी की वजह से परीक्षा को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पश्चिमी प्रांत के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया, देश में विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण पेपर और इंक बाहर से नहीं मंगाया जा सका जिसके कारण कोई भी स्कूल प्रिंसपल परीक्षा को आयोजित नहीं कर सकेंगे।

खबरों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार के इस कदम से देश के दो तिहाई छात्र प्रभावित होंगे। एक अनुमान के तहत श्रीलंका में 45 लाख स्कूली छात्रों की संख्या हैं। श्रीलंका में टर्म टेस्ट एक तरह से फाइनल परीक्षा है जिसमें एसेसमेंट प्रक्रिया से यह तय किया जाता है कि छात्र अगली कक्षा में जा सकते हैं या नहीं। यह साल की आखिरी परीक्षा होती है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार की इतनी कमी हो गई है कि आवश्यक आयात के लिए भी पैसा नहीं जुटाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से इस आर्थिक संकट के कारण आवश्यक भोजन, ईंधन और फार्मास्यूटिकल्स आयात भी रूका हुआ है। श्रीलंका का सबसे बड़ा महाजन चीन से इस आर्थिक संकट से उबारने की गुहार लगा जाने के बावजूद चीन के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

श्रीलंका भारी विदेशी कर्ज तले डूब गया है। सबसे ज्यादा उसने चीन से कर्ज लिया है। लगभग 2।2 करोड़ डॉलर का नगदी संकट तत्काल देश के सामने है। ऐसे में सरकार ने घोषणा की कि वह अपने बिगड़ते विदेशी ऋण संकट को हल करने और विदेशी मुद्र भंडार को बढ़ाने के लिए आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग करेगा। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के अनुरोध पर चर्चा करने करने का आश्वासन दिया है। इस साल श्रीलंका के ऊपर लगभग 6.9 अरब डॉलर के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी है, लेकिन फरवरी के अंत तक इसका विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2.3 अरब डॉलर ही है। इस कारण अन्य आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी है। तेल और खाने-पीने की आवश्यक वस्तुओं के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दूध पाउडर, चीनी, दाल और चावल के राशनिंग के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं। बिजली में भारी कटौती की जा रही है।

सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को हूती विद्रोहियों ने बनाया निशाना

दुबई (ईएमएस)। यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार तड़के सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। हमले में तरल प्राकृतिक गैस संयंत्र, जल विलवणीकरण संयंत्र, तेल प्रतिष्ठान और बिजली केन्द्र को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। यमन में लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने कहा कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन क्षेत्र में असैन्य वाहन और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

यह हमला सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के सीमा पार हमलों में हालिया वृद्धि को दर्शाता है। शांति वार्ता रुकी हुई है और 2015 के बाद से यमन के अधिकांश हिस्सों को बर्बाद करने वाला संघर्ष जारी है। हमले इसलिए भी हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब सरकार समर्थित तेल की दिग्गज कंपनी अरामको ने घोषणा की कि उसका मुनाफा 2021 में 124 प्रतिशत बढ़कर 110 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है, कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक आपूर्ति की कमी, तेल की बढ़ती कीमतों और ईंधन की मांग में सुधार को लेकर नई चिंताओं के बीच मुनाफे में यह एक बड़ी छलांग है।

अरामको जिसे सऊदी अरब तेल कंपनी के रूप में भी जाना जाता है, ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण ऊर्जा बाजारों में तीव्र अस्थिरता के हफ्तों में अपनी कमाई रिपोर्ट जारी की। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक रूस पर दंडात्मक प्रतिबंधों ने पहले से ही मंद ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मचा दी है। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता येहिया सैरी ने कहा कि समूह ने सऊदी अरब के भीतरी क्षेत्र में एक व्यापक और बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था।

सैन्य गठबंधन ने कहा कि उसने अरामको द्वारा संचालित यानबू के लाल सागर बंदरगाह में पेट्रोकेमिकल परिसर में एक तरल गैस संयंत्र पर हमले को विफल कर दिया। हालांकि, तत्काल यह स्पष्ट नहीं है कि हमले से संयंत्र को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। गठबंधन ने कहा कि अन्य हवाई हमलों ने देश के दक्षिण-पश्चिम में एक बिजली स्टेशन, लाल सागर तट पर अल-शकीक में एक विलवणीकरण केंद्र, दक्षिणी सीमावर्ती शहर जिजान में अरामको के एक टर्मिनल और दक्षिणी शहर खमीस मुशैत में एक गैस स्टेशन को निशाना बनाया।

यूक्रेन जंग की तुलना ब्रेक्सिट से करने पर ब्रिटेन के पीएम जॉनसन हुए आलोचना के शिकार

लंदन (ईएमएस)। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की पर रूस की बढ़ती आक्रमकता को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसकी तुलना ब्रेक्सिट की तो उन्हें व्यापक आलोचना का शिकार होना पड़ा। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट ने रविवार को दी। शनिवार को ब्लैकपूल में कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करते हुए जॉनसन ने कहा, ठमैं जानता हूं कि यूक्रेन के लोगों की तरह इस देश के लोगों के पास भी विकल्प है कि वे हर बार आजादी का चुनाव करें। मैं आपको हाल के कुछ मशहूर उदाहरण दे सकता हूं।ठ जब ब्रिटिश लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में ब्रेक्सिट के लिए मतदान किया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वे विदेशियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चीजों को अलग तरह से करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं और इस देश के लिए खुद को चलाने में सक्षम होना चाहते हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनकी टिप्पणी ब्रिटेन और यूरोप में राजनीतिक हस्तियों के बीच अच्छी नहीं रही। गेविन बारवेल ने पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया, उन्होंने कहा, ठउस बिट के अलावा जहां एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह में मतदान किसी भी तरह से अपने देश को आक्रमण से बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने के साथ तुलनीय नहीं है और ये अजीब तथ्य यह है कि यूक्रेनियन यूरोपीय संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं।ठ

रक्षा चयन समिति के अध्यक्ष, कंजर्वेटिव सांसद टोबियास एलवुड ने कहा कि पुतिन के अत्याचार के खिलाफ यूक्रेनी लोगों की लड़ाई की तुलना ब्रेक्सिट के लिए मतदान करने वाले ब्रिटिश लोगों से करना उस राज्य के स्तर को नुकसान पहुंचाता है जिसे हम प्रदर्शित करना शुरू कर रहे हैं। जॉनसन को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' कहते हुए, लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी ने कहा, ठपुतिन के बम से भागने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए जनमत संग्रह की तुलना करना हर यूक्रेनी का अपमान है। वह कोई चर्चिल नहीं हैः वह बेसिल फॉल्टी है।ठ इस बीच यूरोप में यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट किया, ठबोरिस, आपके शब्द यूक्रेनियन, ब्रिटिश और सामान्य ज्ञान को आहत करते हैं।ठ

अमेरिका की हिंद-प्रशांत रणनीति खतरनाक, क्वाड की वजह से एशिया में खड़ा हो सकता है बड़ा संकट : ली यूचेंग

बीजिंग (ईएमएस)। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति को बेहद खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि क्वॉड जैसे समूहों का निर्माण 'उसी तरह से खतरनाक' है, जिस तरह यूरोप में नाटो का विस्तार। चीन के अगले विदेश मंत्री बनने की राह में सबसे आगे चल रहे ली यूचेंग ने कहा कि अमेरिकी नीति एशिया को नरक में ढकेल सकती है।

ली यूचेंग का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब क्वॉड की जापान में बैठक होने वाली है और पीएम मोदी इसमें शामिल हो सकते हैं। ली यूचेंग ने कहा कि यूक्रेन संकट हमें एक आइना दिखाता है कि हम एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हालात का आकलन करें। यह इलाका दो अलग-अलग तरह के विकल्पों का सामना कर रहा है। क्या हमें एक खुला और समावेशी परिवार बनाना चाहिए जो सबके सहयोग पर आधारित हो या फिर हमें छोटे-छोटे ब्लॉक की तरफ बढ़ना चाहिए जो कोल्ड वॉर की मानसिकता और समूहों के बीच संघर्ष पर आधारित है।

चीनी विदेश उप मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीनी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि नाटो के विस्तार ने यूक्रेन संकट को बढ़ाया है। चीन की तरह से भारत ने भी यूक्रेन संकट को लेकर रूस के खिलाफ आए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया है। यही नहीं चीन ने अमेरिका और नाटो को वर्तमान संकट के लिए दोषी ठहराया है। चीन ने कहा कि रूस के वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जाना चाहिए।

चीन और भारत के रुख में रूस को लेकर समानता भले हो लेकिन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। चीन अब नाटो के यूरोप में उठाए गए कदमों को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एशिया में उठाए गए कदमों से जोड़ रहा है। भारत में चीन के राजदूत रह चुके ली चीन के अगले विदेश मंत्री बन सकते हैं और देश के विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्तमान चीनी विदेश मंत्री वांग यी का कार्यकाल अगले साल मार्च में पूरा हो सकता है। उसी समय चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एक नए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में नाटो के कदमों की तुलना एशिया से करके चीन ने चेतावनी दी है कि एशिया में भी इस तरह का संकट पैदा हो सकता है।

ली ने कहा धारा के विपरीत जाकर हिंद-प्रशांत रणनीति का पालन करना समस्या को भड़काएगा। उन्होंने कहा कि अगर इसे बिना रोकटोक के होने दिया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यह अंततः एशिया-प्रशांत क्षेत्र को नरक की सीमा तक ले जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी इसी तरह का बयान दिया था और खासतौर पर अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सदस्यता वाले क्वॉड का जिक्र किया था। उन्होंने क्वॉड की तुलना 'फाइव आइज' से की थी जिसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन हैं।

एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम कर दुनिया का चौधरी बनना चाहता है अमेरिका : लावरोव

मास्को (ईएमएस)। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। लावरोव ने कहा अमेरिका एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम करना चाहता है, जहां अन्य देश उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि यह विचार 'वैश्विक विलेज की नहीं, बल्कि अमेरिकी विलेज की कल्पना को साकार करती है।

उन्होंने कहा इस 'अमेरिकी गांव' को चीन, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको जैसे देश निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। लावरोव ने कहा अमेरिका ने अपने हितों के आधार पर दुनिया को 'एकजुट' किया है। उनका इशारा यूरोपीय संघ और नाटो सदस्य देशों की अमेरिका से वास्तविक 'स्वतंत्रता' की ओर था। उन्होंने कहा कि हालांकि दुनिया का हर देश सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा दुनिया में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी अमेरिकी चौधराहट वाले वैश्विक गांव की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा मुझे भरोसा है कि चीन, भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको जैसे देश खुद को ऐसी स्थिति में नहीं ले जाना चाहेंगे, जहां अंकल सैम उन्हें कुछ करने का आदेश दें और वे इसके जवाब में कहें यस सर। रूसी विदेश मंत्री ने कहा उनका देश उन देशों की श्रेणी में नहीं आता है जो ऐसा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा रूस एक सुरक्षा गारंटी चाहता है जो रूस, यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए समान हो। यूक्रेन में चल रहे हमले के बारे में लावरोव ने कहा कि रूसी सेना का लक्ष्य यूक्रेन का विसैन्यीकरण करना है, ताकि यूक्रेन की तरफ से कभी खतरा पैदा न हो सके। इसके साथ ही सुरक्षा गारंटी हासिल करना चाहता है जो यूक्रेन, रूस और यूरोपीय देशों की समान सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।

लावरोव ने आशा जताई कि रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान 'असमान्य' स्थिति को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि पश्चिमी देश इसे होने से रोक रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा मुझे विश्वास है कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक भाईचारा बना रहेगा। रूसी विदेश मंत्री ने एक बार फिर से यूक्रेन में अमेरिका के जैविक हथियार बनाने के आरोप की ओर इशारा किया।

सिलसिलेवार विस्फोटों से दहला सियालकोट मिलिट्री बेस, मिसाइल विस्फोट से

गोला-बारूद डिपो में लगी आग

सियालकोट (ईएमएस)। पाकिस्तान के सियालकोट में रविवार दोपहर सिलसिलेवार धमाकों की गूंज सुनाई दी। सियालकोट स्थित पाक सेना के गोला-बारूद डिपो में ये ब्लास्ट हुए। पाकिस्तानी सेना के मीडिया एंड पीआर विंग आईएसपीआर ने जानकारी दी कि सियालकोट मिलिट्री बेस में अचानक आग लग गई, जिससे यह हादसा हो गया, हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तरी पाकिस्तान में सियालकोट मिलिट्री बेस पर कई विस्फोट हुए हैं। प्रारंभिक संकेत ये मिल रहे हैं कि यह एक गोला बारूद स्टोरेज एरिया है। धमाके के बाद एक बड़ी आग जलती हुई देखी गई। अभी तक विस्फोट के पीछे की असल वजह का पता नहीं चल पाया है।

लोकल मीडिया के अनुसार पाक सेना द्वारा एयर-टू-एयर मिसाइल पीएल-15 का टेस्ट किया जा रहा था, जो पूरी तरह नाकाम रहा। जे10-सी फाइटर जेट से छोड़े जाने के बाद यह मिसाइल बेकाबू हो गई और सियालकोट में जा गिरी। इस घटना के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से पोस्ट किए गए हैं। सियालकोट छावनी, सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तानी सेना के ठिकानों में से एक, शहर से सटा हुआ इलाका है। इसकी स्थापना 1852 में ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा की गई थी।

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वर्तमान में अपनी सरकार बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दो विपक्षी दलों द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ देश की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इमरान खान अपने ही सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर विद्रोह का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के कम से कम 100 सांसदों ने 8 मार्च को नेशनल असेंबली सचिवालय के समक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की सरकार देश में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है।

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं। जिनमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के सियालकोट आयुध डिपो पर कोई बाहरी चीज पहले आकर गिरी, इसके बाद वहां पर आग लग गई। आयुध डिपो में एक के बाद एक कई बार धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। सियालकोट का कैंटोनमेंट इलाका पाकिस्तानी सेना के सबसे पुराने सैन्य अड्डों में से एक है। यह शहर से पूरी तरह से सटा हुआ है। इसे ब्रिटिश भारतीय सेना ने साल 1852 में बनाया था।

सीजेआई रमण ने वैश्वीकरण में विश्वास बनाने कानून के शासन पर ध्यान देने वाली संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया

दुबई (ईएमएस)। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमण ने यहां कहा कि वैश्विकृत दुनिया में विश्वास पैदा करने के लिए कानून के शासन पर जोर देने वाली मजबूत संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यहां 'वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि कानून का शासन और मध्यस्थता एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। सम्मेलन का आयोजन इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन (आईसीए) द्वारा किया गया और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने इसमें सहयोग किया।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'मध्यस्थता और न्यायिक नैतिकता शिक्षा दोनों का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक ही लक्ष्य की पूर्ति करना है। भारतीय अदालतें अपने मध्यस्थता रुख के लिए जानी जाती हैं।' न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि भारत में अदालतें मध्यस्थता में सहायता करती हैं और निर्णय का पर्याप्त हिस्सा मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए छोड़ देती हैं।उन्होंने कहा, 'बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मध्यस्थता केंद्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र सहयोग करेंगे तथा जानकारी और ज्ञान साझा करेंगे। मैं भारत और दुबई दोनों में एक भविष्य देखता हूं, जो संस्थागत मध्यस्थता की ओर अग्रसर हैं।' प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमण खाड़ी क्षेत्र के अपने पहले दौरे पर हैं।

दुनिया में बढ़ता कोरोना संक्रमण, डब्ल्यूएचओ ने गलत जानकारियों को लेकर जताई चिंता

जेनेवा (ईएमएस)। महामारी कोरोना एक बार कहर बरपा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फैल रही गलत जानकारियों पर चिंता जताई है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दुनिया भर में संक्रमण के मामले बढ़ने के कई कारण हैं और गलत जानकारी भी इनमें से एक है। हाल की में दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देशों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है।

डब्ल्यूएचओ की कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वेन केरकोव ने कहा कि महामारी खत्म हो गई है, ओमिक्रॉन हल्का है और यह कोविड का आखिरी वेरिएंट है, जैसी कई गलत जानकारियां दुविधा पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके चलते वायरस को बढ़ने में मदद मिल रही है। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण पर भी बात की और कहा कि वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौत से बचाने में काफी असरदार है। उन्होंने कहा, 'बाहर हमारे पास भारी मात्रा में गलत जनकारी है। गलत जानकारी कि ओमिक्रॉन हल्का है। गलत जानकारी कि महामारी खत्म हो चुकी है। गलत जानकारी कि यह आखिरी वेरिएंट है, जिसका हमें सामना करना है। यह वास्तव में बहुत दुविधा पैदा कर रहा है।'

केरकोव ने कहा कि बीए.2 अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट नजर आ रहा है। उन्होंने जानकारी दी, 'हमें आबादी के स्तर पर बीए.1 से तुलना में बीए.2 की गंभीरता में कोई बदलाव नजर नहीं आया। हालांकि, ज्यादा मामलों के साथ आप अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या में इजाफा देखेंगे और यह बढ़ी हुई मौतों में बदल जाता है।'

बीते सप्ताह की तुलना में विश्व स्तर पर संक्रमण के नए मामलों में 8 फीसदी इजाफा हुआ है। संगठन के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में हाल ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। यहां मरीजों की संख्या 25 फीसदी और मौतें 27 फीसदी बढ़ गई हैं। कई जानकार इस बात पर चिंता जता चुके हैं कि यूरोप कोरोना वायरस की एक और लहर का सामना कर रहा है। मार्च की शुरुआत से ही ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन में मामलों का बढ़ना जारी है।

ट्रक से शराब पकड़ने वाली कांग्रेस विधायक के खिलाफ किडनैपिंग का केस

-विधायक ने कहा, पुलिस के सामने गैरकानूनी तरीके से गुजरात में शराब लाई जाती है

बनासकंठा(ईएमएस)। राजस्थान से सटे गुजरात के बनासकांठा जिले के वाव की कांग्रेस की विधायक गेनीबेन ठाकोर ने जनता रेड करते हुए एक ट्रक से भारी तादाद में शराब जब्त की। इसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस की नजरों के सामने से ऐसे गैरकानूनी तरीके से गुजरात में शराब लाई जाती है। विधायक और उनके समर्थकों की ओर से किए गए इस जनता रेड में ट्रक ड्राइवर समेत एक अन्य को पकड़ लिया गया और उनकी पिटाई की गई। कुछ देर के लिए दोनों को बैठा कर रखा गया। अब विधायक की जनता रेड को लेकर उनके खिलाफ पुलिस में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है।

उधर, अपने खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद महिला विधायक एक्शन में आ गईं और उन्होंने कहा कि वे इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाएंगी। गेनीबेन ठाकोर ने कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ उनकी ये जंग काफी मजबूत होगी, वे रुकेंगी नहीं। वहीं बनासकांठा के ही कांग्रेस के विधायक गुलाबसिंह का कहना है कि जनता रेड के मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए।

इस पूरे मामले में अब प्रशासन और कांग्रेस के विधायक आमने-सामने आ गए हैं। दरअसल, शराब का अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बजाए विधायक के खिलाफ इस तरह से मामला दर्ज होने को लेकर अब कांग्रेस इस पूरे मामले में आंदोलन के मुड में है। विधायक की जनता रेड के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और 174 स्थानों पर पुलिस ने रेड की। वहीं सोशल मीडिया पर गेनीबेन ठाकोर के खिलाफ एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें महिला विधायक के पति और बेटे पर शराब का व्यापार करने का आरोप लगाया जा रहा है। गेनीबेन ने इस आरोप को लेकर कहा कि अगर मेरे पति और बेटे के खिलाफ शराब बेचने का आरोप है तो उसका सबूत भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के पोस्ट वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं मामला दर्ज कराऊंगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगी। गौरतलब है कि इनदिनों गुजरात में विधानसभा का सेशन चल रहा है। ऐसे में गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने के मुद्दे पर हंगामा होना तय माना जा रहा है।

गुजरात में लगातार घट रहे कोरोन संक्रमण के बीच 24 घंटों में 5 केस बढ़े

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण लगातार घटने से इसके जल्द ही खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी शनिवार को राज्य में कोरोना के 17 नए केस दर्ज हुए थे, जो रविवार बढ़कर 22 पर पहुंच गए हैं वहीं 29 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है राज्य में रिकवरी रेट 99.08 प्रतिशत है दूसरी ओर राज्य में चल रहे टीकाकरण के तहत आज 22574 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया राज्य में फिलहाल कोरोना के 351 सक्रिय मरीजों में 346 स्टेबल हैं और 5 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं जबकि 1212477 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 10939 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में कोरोना के 8 नए मामले दर्ज हुए जबकि राजकोट और वडोदरा कॉर्पोरेशन में 5-5, गांधीनगर और सूरत कॉर्पोरेशन के अलावा तापी और वडोदरा जिले में 1-1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं दूसरी ओर आज राज्य में 22547 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 755 को पहला और 7615 लोगों को दूसरा डोज दिया गया 15 से 18 वर्षीय 227 किशोरों को पहली और 2896 को कोविड की दूसरी वैक्सीन लगाई गई 12 से 14 वर्षीय आयु वर्ग के 9452 किशोरों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया जबकि 1602 नागरिकों को प्रीकॉशन डोज दिया गया राज्य में अब तक कुल 104710591 नागरिकों को वैक्सीनेट किया जा चुका है

होली के इस मौसम में बिखेरें सेहत और पोषण के रंग कैलिफोर्निया वॉलनट्स के संग

सभी भारतीय त्यौहारों में मिठाई का विशेष महत्व होता है और इसे स्वस्थ तरीके से तैयार कर आकर्षित करने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। जब हम रंगों के त्यौहार होली की बात करते हैं, तो कुछ पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेना तो बनता ही है। इस होली, वसंत ऋतु का स्वागत कई रंगों और पौष्टिक व्यंजनों के साथ करें, जो निश्चित रूप से आपके अपनों को लंबे समय तक याद रहेगा।

कैलिफोर्निया वॉलनट से मिठाइयां स्वादिष्ट बनती हैं, जिन्हें आप इस साल अपने प्रियजनों के लिये तैयार कर सकते हैं, वह भी अतिरिक्त पोषण के साथ। और इसका श्रेय वॉलनट (अखरोट) को जाता है। केवल मुट्ठी भर अखरोट (28 ग्राम) प्राकृतिक, पौष्टिक, पौधे-आधारित पोषण प्रदान करते हैं जिसमें 4 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फाइबर और 2.5 ग्राम ओमेगा -3 एएलए शामिल होता है। होली के इन अद्भुत व्यंजनों को बनायें और अपनी होली में और भी रंग भरें।

विपुल चौधरी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया गया

मेहसाणा, २० मार्च ।

मेहसाणा जिले में चौधरी समाज में राजनीति गर्मा गई है । दूधसागर डेयरी के चुनाव में सवा वर्ष पहले विपुल चौधरी की करारी हार के बाद विपुल चौधरी ने पिछले एक महीने से राजनीतिक क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया है । अब विपुल चौधरी ने पामोल की सभा में चौधरी सीनियर हरिभाई चौधरी को गद्दार और अशोक चौधरी को पप्पू कहने पर चौधरी समाज दो हिस्से में बंट गया है । इसी वजह से आज विसनगर तहसील के गुंजा गांव में विपुल चौधरी के समर्थन में सभा आयोजित हुई और विपुल चौधरी के समर्थन में शपथ लिया गया । दूसरी तरफ मेहसाणा तहसील के बोरीयावी गांव में चौधरी समाज के दूसरे दल ने हरिभाई चौधरी और अशोक चौधरी के समर्थन में आंजणा आक्रोश सम्मेलन आयोजित करके विपुल चौधरी के विरूद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया । इस तरह चौधरी समाज में सहकारी क्षेत्र को राजनीतिक रंग लग जाने पर दोनों दल को एक-दूसरे के सामने नाराजगी और नाराजगी व्यक्त की है । राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है ।इसके पहले मेहसाणा जिले के चौधरी समाज में भारी विवाद देखने को मिल रहा है ।जिसमें एक दल विपुल चौधरी के समर्थन में तो दूसरा दल इसके विरोध में है । विपुल चौधरी ने समाज के सीनियरों के खिलाफ किए निवेदन को लेकर एक दल इसका विरोध कर रहा है ।अब आज विपुल चौधरी के समर्थन में चौधरी समाज के एक दल ने शक्ति प्रदर्शन किया । दूसरे दल ने विरोध करने के लिए आक्रोश सभा का आयोजन किया ।

जीपीपी के पूर्व विधायक नलिन कोटडिया भाजपा जॉइन करेंगे, पाटील से की मुलाकात

अहमदाबाद (ईएमएस) राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. केशूभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी (जीपीपी) के विधायक रहे अमरेली जिले के धारी से पूर्व विधायक नलिन कोटडिया फिर एक बार भाजपा जॉइन करेंगे नलिन कोटडिया की गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख सीआर पाटील के साथ मुलाकात के बाद नए समीकरण के संकेत मिल रहे हैं कोटडिया जल्द ही अपने समाज के समर्थक नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे गुजरात विधानसभा के इस साल होनेवाले चुनाव से पहले नलिन कोटडिया के सक्रिय होने से अमरेली राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं गौरतलब है कि भाजपा से अलग होकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी और विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन गुजरात परिवर्तन पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली केशूभाई पटेल जूनागढ़ के विसावदर और नलिन कोटडिया अमरेली जिले की धारी विधानसभा सीट से जीत हुई थी जीपीपी के केवल दो विधायक केशूभाई पटेल और नलीन कोटडिया विधानसभा पहुंचे थे जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों की करारी हार हुई थी चार साल पहले नलिन कोटडिया का नाम बिटकॉइन कांड में आया था समाज के लोगों के साथ भी विश्वासघात किए जाने का नलिन कोटडिया पर आरोप लगा था बिटकॉइन कांड में नाम आनेके बाद कोटडिया भूमिगत हो गए थे बाद में उन्हें जमानत भी मिली और निर्दोष घोषित किए गए थे नलिन कोटडिया का अमरेली में एक बड़ा नाम है और भाजपा में उनके निकट सहयोगी कोटडिया को आगे लाना चाहते हैं सीआर पाटील के साथ मुलाकात के बाद अब कोटडिया की सक्रियता को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं भाजपा प्रमुख सीआर पाटील और नलिन कोटडिया के बीच क्या बात हुई है इसका पता नहीं चला है लेकिन कोटडिया के सक्रिय होने से अमरेली की राजनीति में उठा-पटक संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122, 9327086467 R.N.I. 63177/95